विविध सिविल पूर्ण पीठ

माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. संधावालिया, एम. एस. गुजराल और आर. एन. मित्तल के समक्ष

अमर सिंह, कोर्ट क्लर्क, - याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य,- प्रतिवादी।

1971 की सिविल रिट संख्या 1075।

17 फरवरी, 1976।

भारत का संविधान 1950 - अनुच्छेद 16 (4), 229 और 235 - न्यायालयों के क्लर्क (अब अधीक्षक) जिला और सत्र न्यायाधीशों (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम 1940 - नियम 3 और 4 - जिला न्यायालयों और न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण - क्या ऐसे न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों पर लागू होता है - क्या ऐसे पदाधिकारियों की पदोन्नति - क्या अनन्य रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण के दायरे में - अनुसूचित जातियों के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उच्च पदों के आरक्षण की आवश्यकता वाले सरकारी निर्देश - क्या अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होते हैं - जिला और सत्र न्यायाधीश की स्थापना में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति - चाहे पदोन्नति के माध्यम से - राज्यपाल - क्या नियुक्ति और मंत्रिस्तरीय सेवा की शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति है। अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारी।

भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 235 में, प्रयुक्त शब्दावली "जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय" है और उनका नियंत्रण पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित है। इस शब्दावली का उपयोग पीठासीन न्यायाधीश और उनसे जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को शामिल करने के लिए किया गया है। "जिला अधिकारी और उसके अधीनस्थ न्यायालय" शब्दों के एक सादे व्याकरणिक निर्माण पर। यह इस प्रकार है कि इनमें पीठासीन अधिकारी और उससे जुड़े पदाधिकारियों के बीच किसी भी वित्तीय अंतर के बिना उससे जुड़े सभी व्यक्ति शामिल हैं। अनुच्छेद 235 का बाद का भाग अधीनस्थ न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों को संदर्भित करता है और जिला न्यायाधीश से हीन पदों को धारण करता है। यदि नियंत्रण केवल व्यक्तियों के इस समूह या न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों तक ही सीमित था, तो समग्र रूप से "जिला न्यायालयों" और "उनके अधीनस्थ न्यायालयों" का कोई भी उल्लेख अनावश्यक होगा। इसके अलावा इस तरह का निर्माण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से विध्वंसक होगा, जो निश्चित रूप से संविधान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। कोई भी एक अधीनस्थ न्यायालय के प्रभावी ढंग से कार्य करने की कल्पना नहीं कर सकता है जिसमें पीठासीन अधिकारी अकेले उच्च न्यायालय के नियंत्रण में हो, जबकि अन्य सभी पदाधिकारी और उससे जुड़े प्रशासनिक कर्मचारी न तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में हैं और न ही स्वयं पीठासीन अधिकारी के, बल्कि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और शासित हैं। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालयों के सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी कार्यकरण के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगी। इस प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों तक फैला हुआ है।

(पैरा 10, 11, 13 और 16)।

(बहुमत के अनुसार न्यायमूर्ति संधावालिया और मित्तल, न्यायमूर्ति गुजराल, तत्प्रतिकूल) अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 235 के शुरुआती भाग में "शामिल" शब्द का उद्देश्य किसी भी तरह से अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों के संबंध में उच्च न्यायालय के नियंत्रण के दायरे को कम करना या उनके और उनके पीठासीन अधिकारियों के बीच अंतर की कोई रेखा खींचना नहीं था। अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और उनसे जुड़े पदाधिकारियों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण की प्रकृति और दायरा समान है और संविधान द्वारा दोनों के बीच कोई अंतर और अंतर नहीं किया गया है। यदि पदोन्नति को नियंत्रण के दायरे से बाहर रखा जाता है तो इसकी एक बहुत बड़ी सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। एक लोक सेवक पर नियंत्रण के पीछे वास्तविक मंजूरी अंततः बढ़ावा देने या पदावनत करने की शक्ति है। यदि पदोन्नति की शक्ति की पर्याप्त सामग्री को नियंत्रण से हटा दिया जाता है, तो इसकी पूर्णता समाप्त हो जाएगी और वास्तव में शक्ति आधी हो जाएगी, अगर इसे पूरी तरह से निरर्थक नहीं बनाया जाता है। इस प्रकार, जिला न्यायालयों और न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों की पदोन्नति की शक्ति इसके अधीनस्थ विशेष रूप से उच्च न्यायालय में निहित है और इसके नियंत्रण के दायरे में है।

(पैरा 18, 19 और 21)।

न्यायमुर्ति संधावालिया और मित्तल के बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि जिला और सत्र न्यायाधीश (नियुक्ति और सेवा शर्तें) नियम 1940 के क्लर्क (अब अधीक्षक) के नियम 3 और 4 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जिला और सत्र न्यायाधीश की स्थापना में अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित लिपिक कर्मचारियों के सदस्य हैं जिनके नाम स्वीकृत उम्मीदवारों के रूप में नियम 3 के तहत बनाए गए प्रासंगिक सूची में लाया गया है। ये क्लर्क उसी प्रतिष्ठान के सदस्य या जिला और सत्र न्यायाधीश के तहत अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारी हैं। इसलिए, इनमें से किसी भी व्यक्ति की अदालत के क्लर्क के पद पर नियुक्ति का स्पष्ट रूप से और अस्पष्ट रूप से अर्थ है उच्च रैंक पर पदोन्नति - दोनों स्थिति के आधार पर और जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक के पद से जुड़ी परिलब्धियों के आधार पर। यह नियुक्ति प्राधिकारी के लिए खुला नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को अधीक्षक के पद पर सीधे नियुक्त कर सकता है, चाहे वह कितना भी योग्य या असाधारण योग्यता का क्यों न हो। इस प्रकार, जिला और सत्र न्यायाधीश की स्थापना में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से होती है और यह पहली नियुक्ति के माध्यम से नहीं होती है।

(पैरा 26 और 32)।

न्यायमुर्ति संधावालिया और मित्तल, गुजराल, न्यायमूर्त तत्प्रतिकूल , के बहुमत के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर, उच्च न्यायालय को जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों पर नियंत्रण के साथ निहित किया गया है। इस नियंत्रण में ऐसे सभी पदाधिकारियों को पदोन्नति की शक्ति शामिल है। उच्च न्यायालय ही सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि इनमें से कौन सा पदाधिकारी और अधीनस्थ न्यायालयों का मंत्रालयी कर्मचारी उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त या योग्य है। इसलिए, इस संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी। इन पदाधिकारियों की पदोन्नति का क्षेत्र पूरी तरह से और अनन्य रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण वाले क्षेत्र के भीतर होने के कारण, संविधान के प्रावधानों के मद्देनजर इसमें कोई भी घुसपैठ अनुचित होगी। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में बनाए गए कोई भी अनुदेश या नियम अधीनस्थ न्यायालयों से संबद्ध पदाधिकारियों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उनका एकमात्र नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। यदि इस तरह के कोई निर्देश विशेष रूप से उच्च न्यायालय

के नियंत्रण में आने वाले पदाधिकारियों पर लगाए जाने की मांग की जाती है, तो यह अनुच्छेद 235 द्वारा निहित इस नियंत्रण को बाधित करने के समान होगा और इसलिए, असंवैधानिक होगा। इस प्रकार, उच्च पदों के आरक्षण की आवश्यकता वाले सरकारी अनुदेशों को भरा जाना चाहिए। अनुसूचित जातियों के सदस्यों में से पदोन्नति अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।

(पैरा 34)।

यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल द्वारा उसे सौंपी गई शक्तियों के आधार पर नियम बनाए गए थे क्योंकि इन नियमों को बनाने की शक्ति उसके या उसके नामित व्यक्ति में निहित थी। इन नियमों को बनाने में, उच्च न्यायालय ने राज्यपाल के नामित व्यक्ति के रूप में कार्य किया, भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत राज्यपाल में निहित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की मंत्रिस्तरीय स्थापना की शक्ति के रूप में कार्य किया और उच्च न्यायालय स्वयं या तो ये नियुक्तियां नहीं कर सकता था या नियम नहीं बना सकता था जिसके तहत ये नियुक्तियां की जा सकती थीं। भारत के संविधान ने उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं किया है और अनुच्छेद 309, 310 और 311 इन नियुक्तियों पर भी लागू होंगे। चूंकि अनुच्छेद 310 के परंतुक के तहत राज्य विधानमंडल या राज्यपाल या उनके नामित व्यक्ति द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए राज्यपाल के नामित के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए 1940 के नियम लागू रहेंगे क्योंकि ये संविधान के अनुच्छेद 372 द्वारा बचाए गए हैं और इन नियमों को राज्यपाल के कार्यकारी निर्देशों द्वारा बदला या संशोधित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 235 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह से उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के संबंध में नियम बनाने के राज्यपाल के अधिकार को छीनता हो। इस प्रकार, राज्यपाल के पास उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति है और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों में अनुसूचित जातियों के बीच से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले उच्च पदों के आरक्षण की आवश्यकता होती है, जो अधीक्षक के पद पर नियुक्ति को समान रूप से नियंत्रित करेंगे क्योंकि इन निर्देशों को जारी करना राज्य सरकार की शक्ति के भीतर है। जो जिला और सत्र न्यायाधीश न्यायालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित हैं।

(पैरा 47 और 48)।

न्यायमुर्ति गुजराल ने कहा कि यद्यपि अधीक्षकों के पदों के लिए चयन अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित लिपिक यी कर्मचारियों तक ही सीमित है, लेकिन ये पद नियुक्ति से भरे जाते हैं, पदोन्नति से नहीं और ये पद जिला कैडर के अन्य पदों की तुलना में प्रांतीय कैडर पर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में काम करने वाले क्लर्क के लिए, अधीक्षक के रूप में नियुक्ति इस अर्थ में जीवन में पदोन्नति के बराबर होगी कि उसके पास बेहतर स्थिति और परिलब्धियां होंगी, लेकिन यह उस अर्थ में पदोन्नति के बराबर नहीं होगा जिसमें अनुच्छेद 235 में अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। इस प्रकार अधीक्षक से लेकर जिला और सत्र न्यायाधीश तक का पद नियुक्ति से भरा जाता है, न कि पदोन्नति से। और इन पदों को भरने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है, अनुच्छेद 235 के तहत नियंत्रण की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि राज्यपाल द्वारा उसे सौंपी गई शक्ति के कारण।

(पैरा 50 और 52)।

माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया द्वारा 5 दिसंबर, 1972 को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए डिवीजन बेंच को भेजा गया मामला। न्यायमूर्ति श्री मन मोहन सिंह गुजराल और माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेंद्र नाथ मित्तल की खंडपीठ ने अक्टूबर को सुनवाई की।10 फरवरी, 1974 को इस मामले को पुन पूर्ण पीठ के पास भेज दिया गया और माननीय न्यायमूत श्री एसएस संधावालिया, माननीय न्यायमूत श्री मान मोहन सिंह गुजराल और माननीय न्यायमूर्ति राजेन्द्र नाथ मित्तल की पूर्ण पीठ ने अंततः 11 फरवरी, 1976 को मामले का निर्णय लिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि: –

(१) 16 फरवरी, 1971 (अनुबंध बी) के आदेश को रद्द करने और 11 फरवरी , 1971 के आदेश (अनुबंध बी-1) को खारिज करने और अधीक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने से इनकार करने वाले उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए;

(२) परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाती है जिसमें प्रतिवादियों को अधीक्षक के पद के लिए याचिकाकर्ता पर विचार करने और उसे पंजाब के जिला और सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में अधीक्षक के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाता है।

(च) मामले की परिस्थितियों में कोई अन्य रिट, आदेश या निदेश, जो यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, जारी किया जाए;

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएस मोंगिया के साथ अधिवक्ता कुलदीप सिंह।

मोहिंदरजीत सिंह सेठी, अधिवक्ता अवतार सिंह, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय।

संधावालिया, न्यायमुर्ति

1. पूर्ण पीठ के इस संदर्भ में उठने वाले दो प्रमुख संवैधानिक मुद्दों को निम्नलिखित शब्दों में आसानी से तैयार किया जा सकता है:--

(1) क्या जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा परिकल्पित है , उक्त न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों तक विस्तारित है।

(2) यदि हां, तो क्या ऐसे पदाधिकारियों की पदोन्नति विशेष रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण के दायरे में है।

(3) उपरोक्त को जन्म देने वाले तथ्य और अन्य कानूनी मुद्दे भी गंभीर विवाद में नहीं हैं। याचिकाकर्ता, अमर सिंह, 1944 में सरकारी सेवा में शामिल हुए, लेकिन कार्यपालिका के न्यायपालिका से अलग होने पर, उन्हें 28 फरवरी, 1965 को क्लर्क के रूप में न्यायपालिका में नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया और इस रूप में पुष्टि की गई। और, वर्तमान में, अमृतसर के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय के क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। वह स्नातक हैं लेकिन उनका विशेष दावा यह है कि वह कम्बोज समुदाय से हैं जिसे सरकार ने पिछड़ा वर्ग घोषित किया है। उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड । के अध्याय 18-ए पर भरोसा किया गया है, जिसमें कहा गया है

कि अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए, स्नातक होने वाले क्लर्कों को प्राथमिकता दी जानी है और आगे ऐसी पदोन्नति की जानी है। सहायकों में से चयन के माध्यम से। यह कहा गया है कि अमृतसर जिले में कार्यरत 12 सहायकों में से, याचिकाकर्ता एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पिछड़े वर्ग से है और वरिष्ठता के अनुसार वह नंबर 2 पर है, संपूर्ण सिंह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उससे ऊपर है।

(4) हालांकि, अज्ञात कारणों से, जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को की गई सिफारिश से याचिकाकर्ता का नाम हटा दिया गया है। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया, कि उसका नाम उन व्यक्तियों के पैनल में भी शामिल किया जाना चाहिए, जिन पर अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है, लेकिन उसे सूचित अनुलग्नक 'बी' द्वारा खारिज कर दिया गया था। 12 सितंबर, 1963 और 14 जनवरी, 1964 के पंजाब सरकार के निर्देशों पर याचिकाकर्ता की ओर से विशेष निर्भरता रखी गई है, इस आशय के अनुलग्नक 'सी' और 'सीएल', कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उसमें निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए। यह दावा किया जाता है कि इन निर्देशों के आधार पर, याचिकाकर्ता जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उसे अन्य अधिकारियों की वरीयता में चुना जाना है और इस पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करना जिला और सत्र न्यायाधीश का दायित्व था।

(4) तब यह कहा गया है कि अधीक्षक के एक पद पर पदोन्नति के लिए, जो रिक्त हो गया है, जिला और सत्र न्यायाधीश, अमृतसर ने उपरोक्त संपूर्ण सिंह और कथित मान सिंह के नामों की सिफारिश की है जो याचिकाकर्ता से कथित रूप से कनिष्ठ है। उनका दावा है कि संपूर्ण सिंह केवल मैट्रिक पास हैं, याचिकाकर्ता एकमात्र सहायक हैं जो अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। हालाँकि, अज्ञात कारणों से, याचिकाकर्ता का नाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को की गई अनुशंसा से बाहर कर दिया गया है। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया कि उसका नाम भी उन व्यक्तियों के पैनल में शामिल किया जाना चाहिए जिन्हें अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना है, लेकिन इसे सूचना अनुलग्नक द्वारा खारिज कर दिया गया था। 'बी' उसे बता दिया । 12 सितंबर, 1963 और 14 जनवरी, 1964 के पंजाब सरकार के निर्देशों पर याचिकाकर्ता की ओर से विशेष निर्भरता रखी गई है, इस आशय के अनुलग्नक 'सी' और 'सीएल', कि अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण उसमें निर्धारित पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए । यह दावा किया जाता है कि इन निर्देशों के आधार पर, याचिकाकर्ता जो पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उसे अन्य अधिकारियों की तुलना में प्राथमिकता में चुना जाना है और इस पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश करना जिला और सत्र न्यायाधीश का दायित्व था। वास्तव में, यह मामला है कि याचिकाकर्ता एकमात्र व्यक्ति है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत जारी किए गए अनुलग्नक 'सी' और 'सी 1' के निर्देशों को देखते हुए अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है और जो उच्च पद धारण करने के लिए याचिकाकर्ता को पदोन्नति का अधिमान्य अधिकार प्रदान करते हैं। पदोन्नति के लिए अपने दावे को दोहराने के लिए, याचिकाकर्ता ने 20 फरवरी, 1971 के अनुलग्नक 'डी' के माध्यम से एक और अभ्यावेदन दिया, लेकिन याचिकाकर्ता के दावे के कब्रिस्तान को इसका जवाब भी नहीं दिया गया था कि अनुलग्नक 'सी' और 'सी 1' में निहित सरकारी निर्देशों के आधार पर वह न केवल अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने का हकदार है, बल्कि वास्तव में वह उसी के लिए एकमात्र योग्य उम्मीदवार है।

(5) इस न्यायालय के पंजीयक द्वारा प्रत्यर्थियों की ओर से लिखित कथन दाखिल किया गया है। इसमें याचिका के पैरा 1 से 3 के तथ्यात्मक कथन विरोधाभासी नहीं हैं। तथापि, जहां तक पैरा 4 का संबंध है, यह इंगित किया गया है कि याचिकाकर्ता के मामले में सीधे लागू प्रासंगिक प्रावधान जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के लिपिकों (अब अधीक्षक) की नियुक्ति और नियंत्रण के नियम हैं। उक्त नियमों को वापसी में विस्तार से पुनः प्रस्तुत किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि वास्तव में अमृतसर सत्र प्रभाग में सामान्य लाइन में सहायकों के 10 पद हैं और याचिकाकर्ता नं. वरिष्ठता सूची में 5. यह माना जाता है कि उस जिले में कोई अन्य सहायक पिछड़े वर्ग का नहीं है। अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए की गई सिफारिशों से याचिकाकर्ता के नाम को हटाने का अनुरोध करने का कारण यह है कि जिला और सत्र न्यायाधीश ने उसे पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना और यह भी कि सिविल और आपराधिक कानून में अधिकारी के ज्ञान को पर्याप्त नहीं माना गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि इस विषय पर याचिकाकर्ता के पहले अभ्यावेदन को माननीय मुख्य न्यायाधीश के आदेशों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दूसरे आवेदन का उत्तर नहीं दिया गया था क्योंकि तब तक मामला वर्तमान रिट याचिका दायर करने के कारण विचाराधीन हो गया था। इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के निर्देशों के संबंध में यह कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के सदस्य जिनकी वार्षिक आय 1,800 रुपये से अधिक है, वे अपने पक्ष में दिए गए विशेषाधिकारों का लाभ उठाना बंद कर देते हैं। याचिकाकर्ता की आय अब उस राशि से अधिक हो गई है, इसलिए वह ऐसे किसी अधिमान्य विशेषाधिकार का दावा करने का हकदार नहीं है।

(6) याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल प्रतिवेदन में उन्होंने कमोबेश अपने पहले के रुख को ही दोहराया है। इसके जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा रजिस्ट्रार द्वारा रिकॉर्ड पर रखा गया है जो इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को 20 नवंबर, 1969 को निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत यह निर्देशित किया गया था कि पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नियुक्ति केवल नियुक्ति के पहले चरण में की जानी है, न कि राज्य के भीतर सिविल और सत्र न्यायालयों से जुड़ी सेवाओं में उच्च पद पर पदोन्नति के मामले में।

(7) उपर्युक्त दलीलों से यह स्पष्ट है कि यहां मामले का मूल यह है कि क्या सरकार के निर्देश अनुलग्नक 'सी' और 'सी 1' (जो पदोन्नति के स्तर पर भी अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण प्रदान करते हैं) याचिकाकर्ता की अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के मामले की ओर बिल्कुल भी आकर्षित हैं। यदि ये निर्देश लागू होते हैं तो इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और निर्देश के साथ उनके स्पष्ट संघर्ष का क्या परिणाम होगा कि ऐसा आरक्षण केवल प्रारंभिक चरण में किया जाना है न कि पदोन्नति के बाद के चरणों में।

(8) शुरुआत में ही स्थिति स्पष्ट करने के लिए यह उल्लेख किया जा सकता है कि शुरू में पार्टियों के विद्वान वकील ने इस धारणा पर कुछ तर्क दिए थे कि अनुच्छेद 229 संविधान याचिकाकर्ता के मामले पर भी लागू हो सकता है या लागू हो सकता है। अंततः यह पार्टियों का सामान्य मामला बन गया है कि इस अनुच्छेद का कोई भी अनुप्रयोग नहीं था और सीधे तौर पर प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधान केवल अनुच्छेद 235 था।

मामले या याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 235 के दायरे से पूरी तरह से बाहर करने के लिए, उनके विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने पहले तर्क दिया था कि इस अनुच्छेद में परिकल्पित नियंत्रण सीमित है और केवल राज्य की अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों तक ही सीमित है। वास्तव में तर्क यह है कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण केवल जिला न्यायालयों या उनके अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों

तक फैला हुआ है, न कि उनसे जुड़े पदाधिकारियों या मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों तक। यह तर्क है कि यद्यपि पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी उनके पदाधिकारी और राज्य के नियुक्त कर्मचारी पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और शासित हैं और उन पर उच्च न्यायालय का कोई नियंत्रण नहीं है। अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का निर्देश करने वाले अनुच्छेद 235 के प्रारंभिक भाग का अर्थ केवल जिला न्यायालय का पीठासीन अधिकारी और उससे निम्न न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी हैं।

(9) चूंकि विवाद अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 235 की भाषा के आसपास घूमना चाहिए, इसलिए पहले इसे संदर्भ में आसानी के लिए निर्धारित करना उचित है।

"235. जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, जिसमें किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश के पद से हीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और उन्हें अनुमति प्रदान करना शामिल है, उच्च न्यायालय में निहित होगा, लेकिन इस अनुच्छेद की किसी भी बात का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से अपील का कोई अधिकार छीनने के रूप में नहीं लगाया जाएगा जो उसे अपनी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली कानून के तहत हो सकता है या उच्च न्यायालय को ऐसी कानून के तहत निर्धारित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार अन्यथा उससे निपटने के लिए अधिकृत करता है।

(10) यहां सबसे पहली बात यह है कि उपरोक्त उद्धृत अनुच्छेद के प्रारंभिक भाग में प्रयुक्त शब्दावली "जिला न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालय" है और उनका नियंत्रण पूरी तरह से उच्च न्यायालय में निहित किया गया है। मेरा मानना है कि इस शब्दावली का उपयोग पीठासीन न्यायाधीश और उनसे जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को शामिल करने के लिए किया गया है। यदि संविधान निर्माताओं का इरादा उच्च न्यायालय के नियंत्रण को केवल जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों तक सीमित करना था, तो इस तरह की व्यापक शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाता। वास्तव में, तब उपयुक्त भाषा "जिला न्यायाधीश और उनके अधीनस्थ न्यायाधीश" होती। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि पूर्ववर्ती अनुच्छेद 233 और 234 में जिला न्यायाधीश शब्द का प्रयोग किया गया था और इसलिए, यह इस प्रकार है कि जब अनुच्छेद 235 में भाषा को "जिला न्यायालय" अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए बदल दिया गया था, तो यह अर्थहीन नहीं था। "जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालय" शब्दों के एक सादे व्याकरणिक निर्माण पर यह प्रतीत होता है कि इसमें पीठासीन अधिकारी और उससे जुड़े पदाधिकारियों के बीच किसी भी भेद के बिना इससे जुड़े सभी व्यक्तियों को समग्र रूप से शामिल किया जाना चाहिए।

(11) जब संविधान के अनुच्छेद 235 के बाद के भाग का भी संदर्भ दिया जाता है तो उपर्युक्त निष्कर्ष को और मजबूत किया जाता है। यह, संदर्भ में, अधीनस्थ न्यायिक सेवा से संबंधित और जिला न्यायाधीश से कम पदों पर आसीन व्यक्तियों को संदर्भित करता है। यदि नियंत्रण केवल व्यक्तियों के इस समूह या न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों तक ही सीमित था, तो धारा के प्रारंभिक भाग में समग्र रूप से "जिला न्यायालयों" और "उनके अधीनस्थ न्यायालयों" का कोई भी उल्लेख अनावश्यक और भ्रामक दोनों होगा। यदि ऐसा कोई आशय व्यक्त किया जाना था तो अनुच्छेद 235 को इसके प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से तैयार किया जा सकता था-"किसी राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों और जिला

न्यायाधीश के पद से हीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों पर नियंत्रण (जिसमें ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति और अनुमति देना शामिल है) उच्च न्यायालय में निहित होगा, लेकिन कुछ भी नहीं....."

वास्तव में, श्री कुलदीप सिंह ने जिस निर्माण के लिए प्रचार किया था, उस पर "जिला न्यायालय" और "उसके अधीनस्थ न्यायालय" शब्दों का उपयोग केवल अधिशेष और एक पेटेंट अतिरेक बन जाएगा। यह निर्माण का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी कानून के किसी भी हिस्से की व्याख्या केवल अधिशेष के रूप में नहीं की जानी चाहिए या बहुत ही सम्मोहक कारणों को छोड़कर उसके पर्याप्त हिस्से को अन्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। संविधान की व्याख्या करते समय ऐसा इसलिए अधिक होता है क्योंकि संस्थापकों ने बिना किसी सार्थक उद्देश्य के इन शब्दों का उपयोग नहीं किया होता।

(12) ऐतिहासिक रूप से भी, भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 254 और 255 का एक पारित संदर्भ देना शिक्षाप्रद है, जो एक तरह से पूर्ववर्ती प्रावधान प्रतीत होते हैं और संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 233,234 और 235 के अनुरूप हैं। इस संदर्भ में पंजाब राज्य बनाम ओम प्रकाश धारवाल की पूर्ण पीठ के मामले में बहुमत के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है और दूसरा, (1). उपर्युक्त धाराओं में, जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धाराओं की भाषा और सार से एक स्पष्ट विचलन किया गया था, जिसमें जिला न्यायालयों के साथ-साथ संविधान के संबंधित अनुच्छेदों में उनके अधीनस्थ न्यायालयों के विशेष संदर्भ के साथ उच्च न्यायालय का नियंत्रण शुरू किया गया था। यह स्पष्ट रूप से पहले के प्रावधानों से विचलित होने के लिए बनाया गया था और व्यक्त परिवर्तन को या तो शब्दों को केवल अधिशेष के रूप में समझकर या उनके अर्थ को इस तरह सीमित और सीमित करके वस्तुतः निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है कि इन न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के अलावा और कुछ भी इसके दायरे में शामिल न हो।

XI) । ^ R. 1972 (2) पीबी। और हरियाणा 289.

(13) सैद्धांतिक रूप से भी हम यह तर्क पाते हैं कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण केवल पीठासीन अधिकारियों तक ही सीमित है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से विध्वंसक होगा जो कि संविधान के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। एक अधीनस्थ न्यायालय के प्रभावी ढंग से कार्य करने की कल्पना नहीं की जा सकती है जिसमें अकेले पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है जबकि अन्य सभी पदाधिकारी और उससे जुड़े प्रशासनिक कर्मचारी न तो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में हैं और न ही पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में हैं, बल्कि पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और शासित हैं। मुझे व्यवहार में ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालयों के सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी कामकाज के लिए पूरी तरह से विनाशकारी प्रतीत होती है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का तर्क एक ही अधीनस्थ न्यायिक न्यायालय के भीतर एक द्वैत नियंत्रण को प्रस्तुत करता है। इस तरह की स्थिति को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2) के हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके प्रभुओं द्वारा अस्वीकृत और अपमानित किया गया है . बी आर गुलियानी बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कुलसचिव (3) के माध्यम से पूर्ण पीठ के फैसले में निम्नलिखित शब्दों में इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था-

"अनुशासनात्मक नियंत्रण को दो प्राधिकरणों, अर्थात् उच्च न्यायालय और राज्यपाल के बीच विभाजित नहीं किया जा सकता है।"

वास्तव में, यह अभिनिर्धारित करने के लिए किसी बड़ी विद्वता की आवश्यकता नहीं है कि जब तक अपने अधिकारियों पर प्रभावी नियंत्रण और शक्ति नहीं है, कोई भी न्यायालय कानून द्वारा उसे दिए गए कार्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकता है।

(2) A LR 1975 s c 613।

(3) A.I.R. 1975 Pb. हरियाणा 265 (F.B.).

(14) संविधान के अनुच्छेद 229 का सादृश्य भी अवश्य ही ध्यान में आता है। स्वयं उच्च न्यायालय के संदर्भ में उसके प्रशासनिक कर्मचारियों को पूरी तरह से मुख्य न्यायाधीश की शक्ति और नियंत्रण के भीतर रखा गया है, जिसमें नियुक्ति और बर्खास्तगी आदि की शक्ति और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण भी शामिल है। जहां तक जिला न्यायालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का संबंध है, संविधान ने इतना आगे नहीं बढ़ाया और इसके बजाय अनुच्छेद 235 के आधार पर उच्च न्यायालय को इस पर नियंत्रण सौंप दिया। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उच्च न्यायालयों और उनके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से अपने मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों पर शक्तियों और नियंत्रण से वंचित कर दिया जाएगा। मेरा विचार है कि क़ानून की स्पष्ट भाषा के अलावा ऐसी कोई व्याख्या सिद्धांत रूप में अस्थिर प्रतीत होती है।

(15) श्री कुलदीप सिंह ने काफी हद तक स्वीकार कर लिया था कि वह जिस विचित्र प्रस्ताव को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसके लिए वह किसी अधिकार का हवाला नहीं दे सकते। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए विवाद के खिलाफ मैं जो दृष्टिकोण लेता हूं, वह पूर्ववर्ती से समर्थन पाता है। मोहम्मद गौस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (4) पीठ की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति जगनमोहन रेड्डी ने स्पष्ट शब्दों में कहा हैः-"याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि अनुच्छेद 235 में प्रयुक्त 'न्यायालय' शब्द उस व्यक्ति पर नियंत्रण का संकेत नहीं देता है जो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। हमें इस तर्क को असमर्थनीय मानते हुए खारिज कर देना चाहिए। अनुच्छेद 227 और 235 दोनों में, 'न्यायालय' शब्द का उपयोग किया गया है और यह नहीं कहा जा सकता है कि संविधान निर्माताओं ने इस शब्द का उपयोग उन न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों या उन न्यायालयों के अन्य पदाधिकारियों को शामिल करने के लिए नहीं किया था। जबकि 'न्यायाधीश' शब्द का उपयोग केवल व्यक्ति को ही दर्शाता है, 'न्यायालय' शब्द का उपयोग जब किया जाता है तो इसमें न केवल उस न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति शामिल होता है, बल्कि उस न्यायालय के सभी पदाधिकारी और उससे संबंधित कोई भी मामला भी शामिल होता है। इस शब्द के सामान्य अर्थ में न केवल वह भवन शामिल है जिसमें न्यायालय आयोजित किया जाता है, बल्कि न्यायाधीश और अधिकारी भी शामिल हैं जो वहां अध्यक्षता करते हैं।

उपर्युक्त दृष्टिकोण को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रसिद्ध मामले नृपेंद्र नाथ बागची बनाम पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव (5) में पूर्ण पीठ द्वारा अनुमोदित और अनुसरण किया गया थाः-"यह मामला फिर आंध्र उच्च न्यायालय में वापस आया और आंध्र उच्च न्यायालय का अगला निर्णय मोहम्मद गौसा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (6) में बताया गया है जिसमें कहा गया है कि (1)" न्यायालय "शब्द में उन न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति और उन न्यायालयों के अन्य पदाधिकारी शामिल हैं और (2) उच्च न्यायालय को निश्चित रूप से न्यायिक अधिकारियों के आचरण की जांच करने का अधिकार क्षेत्र है और यह स्पष्ट है कि यह केवल यह पता लगाने के उद्देश्य से प्रारंभिक जांच करने तक ही सीमित नहीं है कि

क्या आरोप का जवाब देने के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला है। हम आंध्र उच्च न्यायालय के इन दो फैसलों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

जैसा कि सर्वविदित है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय की बाद में उनके लॉर्डशिप्स द्वारा पुष्टि की गई और इसे पश्चिम बंगाल राज्य और दूसरे बनाम नृपेंद्र नाथ बेगची(7) के रूप में रिपोर्ट किया गया । वास्तव में, उस निर्णय में भी निम्नलिखित टिप्पणियां फिर से उस दृष्टिकोण का समर्थन करती प्रतीत होती हैं जो मैं लेने के लिए इच्छुक हूंः-

'जिला न्यायाधीशों के मामले में, व्यक्तियों की नियुक्ति और नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा की जानी है, लेकिन जिला न्यायाधीश पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि इस्तेमाल किया गया शब्द "जिला न्यायालय" है क्योंकि शेष लेख स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि "न्यायालय" शब्द का उपयोग न केवल उचित न्यायालय बल्कि पीठासीन न्यायाधीश को भी दर्शाने के लिए किया जाता है। अनुच्छेद 235 का उत्तरार्द्ध भाग उस व्यक्ति की बात करता है जो पद संभालता है।"

(6) A.I.R. 1959 आंध्र प्रदेश 497.

(7) A.I.R. 1966 S.C. 447.

(16) सिद्धांत और मिसाल के महत्व के आधार पर मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण पूरी तरह से पीठासीन अधिकारियों और जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों और मंत्रालयिक कर्मचारियों तक फैला हुआ है। अपने पहले बिंदु पर खारिज किए जाने पर, श्री कुलदीप सिंह ने तर्क दिया कि भले ही यह मान लिया जाए कि उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों के पदाधिकारियों तक फैला हुआ है, फिर भी यह नियंत्रण इसके दायरे में नहीं आएगा। इन पदाधिकारियों की पदोन्नति यह तर्क दिया गया कि पदोन्नति नियंत्रण क्षेत्र के बाहर थी न कि उसके भीतर। यह तर्क देने के लिए कि एक ओर न्यायिक सेवा के सदस्यों और दूसरी ओर इन न्यायालयों से संबद्ध अधिकारियों के बीच इस संबंध में अंतर मौजूद है, अनुच्छेद 235 के प्रारंभिक भाग में “सहित” शब्द के उपयोग से कुछ समर्थन मांगा गया था। वकील ने प्रस्तुत किया कि यह अनुच्छेद 235 द्वारा पदोन्नति की शक्ति के व्यक्त प्रदान के आधार पर था कि राज्य की न्यायिक सेवा के सदस्यों को इसके दायरे में लाया गया था। यह कहा गया था कि अन्यथा पदोन्नति की शक्ति नियंत्रण सरलीकरणकर्ता के दायरे में नहीं थी।

(17) मैं याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ हूं। अनुच्छेद 235 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की प्रकृति और दायरे को उनके आधिपत्य के कई निर्णयों में विस्तृत किया गया है, जिसका विस्तृत संदर्भ अनावश्यक है . यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि एक दशक पहले भी नृपेंद्र नाथ बागची के मामले AIR 1966 SC 447 में, हिदायतुल्ला, जे., (जैसा कि उनका आधिपत्य तब था) बेंच के लिए बोलते हुए निम्नानुसार कहा गया था:--

"शब्द 'नियंत्रण' जैसा कि हमने देखा, संविधान में पहली बार इसका प्रयोग किया गया और इसके साथ 'वेस्ट' शब्द भी जुड़ा है। जो एक सशक्त शब्द है. यह दर्शाता है कि उच्च न्यायालय को न्यायपालिका पर नियंत्रण का एकमात्र संरक्षक बना दिया गया है।"

उच्च न्यायालयों के नियंत्रण की पूर्णता और उसके आधार पर अपने अधीनस्थ न्यायालयों और उनसे जुड़े पदाधिकारियों पर विशेष अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना अब वस्तुतः स्थापित कानून बन गया है।

(18) मुझे इस कथन में कोई सार नहीं मिला कि शब्द "सहित" अनुच्छेद 235 के प्रारंभिक भाग में किसी भी तरह से अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों के संबंध में नियंत्रण के दायरे में कटौती करने या किसी को आकर्षित करने का इरादा था उनके और उनके पीठासीन अधिकारियों के बीच अंतर की रेखा। इस शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से नियंत्रण के दायरे को विस्तार देने और स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि मामले को विवाद से परे रखा जा सके। विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस शब्द का उपयोग अनुच्छेद 233 और 234 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के कारण किया जाना था, जिसमें उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और नियुक्ति और पदोन्नति निहित है। अनुच्छेद 234 में लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार अधीनस्थ न्यायपालिका की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। इन पूर्ववर्ती उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, अनुच्छेद 235 में यह स्पष्ट किया गया था कि जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों का जिला न्यायाधीश के पद से हीन पद धारण करने का संबंध है, उनकी नियुक्ति, पदोन्नति और अवकाश प्रदान करना उच्च न्यायालय के नियंत्रण में था। मेरा यह मानना है कि अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों और उनसे जुड़े अधिकारियों पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण की प्रकृति और परिधि समान है और दोनों के बीच कोई भेद और अंतर संविधान के निर्माताओं द्वारा न तो अभिप्रेत था और न ही विचार किया गया था।

(19) उत्तरदाताओं की ओर से श्री सेठी ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 में निश्चित रूप से इसके दायरे में कार्यकर्ताओं की पदोन्नति या तो उच्च परिलब्धियों के माध्यम से या उच्च रैंक के पद पर नियुक्ति द्वारा शामिल है। सैद्धांतिक रूप से उन्होंने कहा कि यदि पदोन्नति को नियंत्रण के दायरे से बाहर रखा जाता है तो इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। यदि किसी अधिकारी के पास उसकी पदोन्नति के संबंध में कोई शक्ति या अधिकार नहीं है तो वास्तविक व्यवहार में उसके अधीनस्थ पदाधिकारी पर किसी प्राधिकारी का नियंत्रण क्या होगा? यह कहा जा सकता है कि एक लोक सेवक पर नियंत्रण के पीछे वास्तविक मंजूरी अंततः पदोन्नत करने या पदावनत करने की शक्ति है। यदि पदोन्नति की शक्ति की सारभूत सामग्री को नियंत्रण से हटा दिया जाता है, तो उसकी पूर्णता, जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अक्सर दोहराया गया है, का अवमूल्यन किया जाएगा और वास्तव में एक अर्थ में शक्ति आधी हो जाएगी, यदि पूरी तरह से निरर्थक नहीं किया जाता है।

(20) यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि वह अपने प्रस्ताव के समर्थन में किसी भी प्राधिकरण का हवाला नहीं दे सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 में परिकल्पित नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों की पदोन्नति तक विस्तारित नहीं था। इसके विपरीत, श्री सेठी सत्य कुमार और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (8) A.I.R. 1971 A.P. 320 में खंड पीठ की भारी टिप्पणियों के साथ अपने तर्क को निम्नलिखित प्रभाव से पुष्ट करने में सक्षम हैंः - * * *। इसका स्पष्ट अर्थ है कि उप-न्यायाधीश के पद पर जिला मुन्सिफ की पदोन्नति उच्च न्यायालय में निहित है क्योंकि 'नियंत्रण' शब्द में पदोन्नति भी शामिल है। इस अनुच्छेद के कारण ही नियम 2 (1) में कहा गया है कि ऐसी पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी।

उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुँचने में पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय, कलकत्ता और दूसरे

बनाम अमल कुमार राय और अन्य (9) A.I.R. 1962 S.C. 1704. में किए गए अनुपात और टिप्पणियों पर भरोसा किया था और उनसे समर्थन प्राप्त किया था । मेरा विचार है कि उपरोक्त दृष्टिकोण का और सुदृढ़ीकरण असम राज्य में कानून के हालिया उच्चारण और एक अन्य बनाम एस के सेन और एक अन्य (10) A.I.R. 1972 S.C. 1028. द्वारा प्रदान किया गया है। उसमें संविधान पीठ ने नृपेंद्र नाथ बागची (उपर्युक्त) और असम राज्य बनाम हेंग मोहम्मद (11) A.I.R. 1967 S.C. 908. के पूर्ववर्ती मामलों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शब्दों में निष्कर्ष निकाला हैः - "* * * परिणाम यह है कि हमारा मानना है कि जिला न्यायाधीश से निम्न पदों पर आसीन व्यक्तियों की पदोन्नति की शक्ति उच्च न्यायालय में होने के कारण ऐसी पदोन्नति की पुष्टि करने की शक्ति उच्च न्यायालय में भी है। हमारा यह भी मानना है कि जहां तक नियम 5 (iv) संविधान के अनुच्छेद 235 के साथ टकराव में है, इसे अमान्य माना जाना चाहिए।

अनुच्छेद 235 के अंतिम भाग के आधार पर, एक तर्क दिया गया था कि पदोन्नति के रूप में उच्च न्यायालय की शक्ति सीमित थी। इस लेख के पहले भाग के सादे शब्दों को देखते हुए, इस तर्क का कोई आधार नहीं है।"

(21) उपरोक्त आधिकारिक कथन के आलोक में, मैं यह मानूंगा कि जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े सभी पदाधिकारियों की पदोन्नति की शक्ति विशेष रूप से उच्च न्यायालय में निहित है।

(22) एक सहायक संवैधानिक मुद्दा, जो वर्तमान मामले में प्रासंगिक है, को भी संक्षेप में संदर्भित किया जा सकता है। पदोन्नति के स्तर पर अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण देने वाले राज्य सरकार के निर्देश, अनुलग्नक 'सी' और 'सी-1' भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 के उपखंड (4) से प्राप्त शक्ति के तहत जारी किए जाते हैं। तर्क की शुरुआत में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने एक कमजोर तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय को अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के पक्ष में सेवाओं में आरक्षण के मामले के संबंध में कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए एक राज्य की परिभाषा के भीतर नहीं आता था। हालांकि, यह श्री कुलदीप सिंह के श्रेय के लिए कहा जाए कि उन्होंने इस तर्क को बिना किसी शर्त के वापस ले लिया और स्वीकार किया कि उच्च न्यायालय को निश्चित रूप से भारत के संविधान के भाग III में अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए 'राज्य' शब्द में शामिल किया जाएगा। इसलिए, मैं वर्तमान मामले में इस स्वीकृत धारणा पर आगे बढ़ रहा हूं कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रयोजनों के लिए एक राज्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत नियुक्तियों के आरक्षण के लिए समान रूप से निर्देश जारी कर सकता है। इस मामले में दिनांक 20 नवंबर, 1969 का प्रासंगिक निर्देश, इसलिए, उपर्युक्त प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर दिया गया है। इसने निर्देश दिया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण केवल प्रारंभिक भर्ती के स्तर पर होगा न कि पदोन्नति के स्तर पर। याचिकाकर्ता की ओर से, इस प्रकार, यह स्वीकार किया जाता है कि उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर इस प्रकार के निर्देश जारी करने की शक्ति होगी।

(23) तथापि, श्री सेठी के प्रति निष्पक्षता में, वास्तव में यह आवश्यक नोटिस है कि उन्होंने बलपूर्वक यह तर्क दिया था कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के राज्य होने या न होने का प्रश्न केवल याचिकाकर्ता की रियायत पर आधारित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रस्ताव उच्च प्राधिकारी द्वारा अच्छी तरह से स्थापित किया गया था। इस संदर्भ में उनके द्वारा (सरमा शरन और

एक अन्य बनाम माननीय मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य) (12) A.I.R. 1964 राजस्थान 13. में स्पष्ट टिप्पणियों का संदर्भ दिया गया था और सादृश्य के माध्यम से समर्थन की मांग (राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड, जयपुर बनाम मोहन लाई और अन्य) (13)) A.I.R. 1967 S.C. 1857.और शेख्रीवम्मदा नल्ला कोवा बनाम प्रशासक, लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनदीवी द्वीप समूह, कोड़िकोड और अन्य केंद्र शासित प्रदेश) (14) A.I.R. 1967 केरल 259 से की गई थी। यद्यपि ये मामले श्री सेठी द्वारा प्रचार किए गए प्रस्ताव को काफी समर्थन देते हैं, लेकिन मैं संवैधानिक क्षेत्र में उस बिंदु पर एक सुविचारित राय का उच्चारण करना अनावश्यक और शायद असुरक्षित मानता हूं जहां हमारे सामने विपरीत दृष्टिकोण नहीं रखा गया है। इस मामले के प्रयोजनों के लिए, रियायत और इस स्वीकृत स्थिति पर आगे बढ़ना पर्याप्त है कि उच्च न्यायालय एक राज्य है और इस प्रकार, अनुच्छेद 16 के खंड (4) के आधार पर निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है।

(24) संवैधानिक आधार साफ हो जाने के बाद अब मैं एकमात्र कानूनी मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता हूं जो कि शेष है, अर्थात्, क्या जिला और सत्र न्यायाधीश की स्थापना में अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से है या नहीं। यहां भी अंतिम चरण में एक बहुत बड़ा क्षेत्र अब विवाद में नहीं है। इस न्यायालय के पंजीयक द्वारा प्रत्यर्थियों की ओर से लिया गया दृढ़ रुख यह था कि मामले को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक प्रावधान जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के लिपिकों (अब अधीक्षक) की नियुक्ति और नियंत्रण से संबंधित नियम हैं। इन नियमों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इन नियमों को वापसी में विस्तार से उद्धृत किया गया है। दलीलों के प्रारंभिक चरण में याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री कुलदीप सिंह ने इन नियमों के स्रोत और वैधता दोनों पर हमला किया था। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील को एक अतिरिक्त हलफनामा देने का निर्देश दिया और तदनुसार इस न्यायालय के उप-पंजीयक (नियम और सामान्य प्रशासन) ने इतिहास और वर्तमान मामले में इन नियमों के अनुप्रयोग के संबंध में शपथ ली है। इसके बाद उक्त हलफनामे में लिए गए तथ्यों और स्थिति को याचिकाकर्ता की ओर से विवादित नहीं किया गया था। विशेष रूप से, यह ध्यान देने योग्य है कि इन नियमों की वैधता को वर्ष 1947 में श्री राम रंग (अब इस न्यायालय के एक अधिवक्ता) और अन्य लोगों द्वारा पांच सेवा अपीलों के माध्यम से चुनौती का विषय बनाया गया था। मुद्दों का महत्व और उनकी जटिलता तेजा सिंह जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। एक सुविचारित निर्णय में ए.एन. भानदारी जे. (जैसा कि उस समय उनका आधिपत्य था) और मोहम्मद मुनीर जे. की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले दिनांक 16 जुलाई, 1947 द्वारा, इन नियमों की वैधता को बरकरार रखा और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के आधार पर किसी भी चुनौती को खारिज कर दिया । इस निर्णय के त्रुटिहीन तर्क, जिसके साथ याचिकाकर्ता की ओर से उसके विद्वान वकील द्वारा सहमति भी नहीं दी गई है। वास्तव में उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, श्री कुलदीप सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उपरोक्त नियम अब विवाद के दायरे से बाहर थे और जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा कि उन्होंने वास्तव में इस संदर्भ में अपनी दलीलों के समर्थन में उन पर भरोसा किया था। इसलिए, मैं इस मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि क्या अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से है या अन्यथा इस मुद्दे पर वैधानिक नियमों के आलोक में है। इस निर्णय के त्रुटिहीन तर्क, जिससे हम सहमत हैं, की याचिकाकर्ता की ओर से उसके विद्वान वकील ने भी आलोचना नहीं की है। वास्तव में उपर्युक्त पृष्ठभूमि में श्री कुलदीप सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था कि उपरोक्त नियम अब विवाद के दायरे से परे हैं और जैसा कि इसके बाद देखा जाएगा, वास्तव में, उन्होंने इस संदर्भ में अपने तर्कों के समर्थन में उन

पर भरोसा किया था। इसलिए, मैं इस मुद्दे की जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि क्या अधीक्षक के पद पर नियुक्ति पदोन्नति के माध्यम से है या अन्यथा इस बिंदु पर वैधानिक नियमों के आलोक में है।

(25) अब जिला एवं न्यायालयों के लिपिकों (अब अधीक्षकों) के प्रासंगिक प्रावधान; वर्तमान मामले के लिए सत्र न्यायाधीश (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम उसके नियम 3 और 4 हैं। इसलिए इन्हें निर्धारित किया जा सकता है:

नियम 3. उम्मीदवारों का नामांकन

"जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय के क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृत उम्मीदवारों की एक सूची उच्च न्यायालय द्वारा रखी जाएगी। यह सूची गोपनीय होगी और किसी भी व्यक्ति को यह सूचित करना आवश्यक नहीं होगा कि उसका नाम इसमें जोड़ा गया है या हटा दिया गया है। ....."

नियम 4. योग्यताएँ.

''जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के क्लर्क के पद पर नियुक्ति केवल नियम 3 के तहत स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची से की जाएगी। इन उम्मीदवारों का चयन अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों के अनुपात में किया जाएगा। 50% मुस्लिम, 30% हिंदू और अन्य और 20% सिख।"

पारित करते हुए, यह देखा जा सकता है कि शायद नियम 4 का उत्तरार्द्ध, सेवा में सांप्रदायिक आरक्षण तय करना, संविधान के बाद के युग में वैध नहीं हो सकता है। हालाँकि, जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, यह मुद्दा बिल्कुल भी नहीं उठता है।

(26)उपर्युक्त उपबंधों को सीधे पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि ये नियम विशेष रूप से न्यायालय के लिपिक के पद पर सीधी नियुक्ति पर रोक लगाते हैं, जिसे अब अधीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया है। इस प्रकार, किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय के लिपिक के पद पर नियुक्त करने के लिए, चाहे वह कितना भी योग्य या असाधारण योग्यता का क्यों न हो, यह नियुक्ति प्राधिकारी, अर्थात् अकेले उच्च न्यायालय के लिए खुला नहीं है। सेवा कानून में, उन पदों का एक पेटेंट और अच्छी तरह से स्थापित विशिष्टता है जिन्हें सीधे नियुक्ति द्वारा भरा जाना है, जो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले पदों से काफी अलग हैं। इस प्रकार, प्रत्यक्ष नियुक्ति और पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति में एक अच्छी तरह से समझा गया अंतर है। जहां नियुक्ति प्राधिकारी को खुले बाजार से सीधे किसी व्यक्ति को पद पर नियुक्त करने का अधिकार है, वहां ऐसी शक्ति प्रत्यक्ष नियुक्ति की शक्ति होगी। दूसरी ओर, जहां ऐसा कोई अधिकार वर्जित है और किसी उच्च पद पर नियुक्ति केवल निचले पदों पर आसीन व्यक्तियों में से चयन की प्रक्रिया द्वारा की जानी है, तो ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की दूसरी श्रेणी में आती है। इसलिए नियम 3 और 4 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि पद पर पदोन्नति के लिए पात्र व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित लिपिक कर्मचारियों के सदस्य हैं, जिनके नाम नियम 3 के तहत बनाए गए प्रासंगिक सूची में स्वीकार किए गए उम्मीदवारों के रूप में लाए गए हैं। यह कि ये लिपिक एक ही प्रतिष्ठान के सदस्य हैं या जिला और सत्र न्यायाधीशों के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारी हैं, विवाद का विषय नहीं है। अतः इनमें से किसी भी व्यक्ति की न्यायालय के लिपिक के पद पर नियुक्ति का स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से तात्पर्य जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक के पद से जुड़ी स्थिति और परिलब्धियों दोनों के आधार पर उच्च पद पर पदोन्नति से है। इसलिए, मैं प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों से निष्कर्ष निकालता हूं कि इस नियम के

आधार पर अधीक्षक के पद पर नियुक्ति स्पष्ट रूप से पदोन्नति के माध्यम से होती है और संभवतः इसे उसी के लिए प्रत्यक्ष या पहली नियुक्ति नहीं कहा जा सकता है।

(27) प्रत्यर्थियों की ओर से श्री सेठी ने तब इस तथ्य को सही ढंग से रेखांकित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं रिट याचिका में अपने अभिकथनों में स्पष्ट शब्दों में स्थापित एकमात्र मामला यह था कि वह केवल पदोन्नति के माध्यम से न्यायालय के क्लर्क के पद का हकदार था। याचिकाकर्ता के स्वयं के प्रदर्शन पर वह लगभग 30 साल पहले एक क्लर्क के रूप में सरकारी सेवा में शामिल हुआ था और किसी भी मामले में लगभग एक दशक पहले 1965 में अधीनस्थ न्यायिक प्रतिष्ठान को आवंटित किया गया था। वकील के माध्यम से दायर की गई अच्छी तरह से तैयार की गई रिट याचिका के संदर्भ से यह स्पष्ट होता है कि मामला पूरी तरह से स्थापित था कि याचिकाकर्ता या तो न्यायालय के क्लर्क के पद पर पदोन्नत होने का हकदार था या वैकल्पिक रूप से कम से कम ऐसी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार था। पैराग्राफ 4 में, यह कहा गया है कि अधीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए क्लर्क जो स्नातक थे, उन्हें वरीयता दी जानी थी और याचिकाकर्ता ने इस आधार पर पदोन्नति के इस अधिकार का दावा किया कि वह स्नातक था और पहले से ही सहायक के रूप में काम कर रहा था। पैरा 6 में फिर से स्पष्ट अभिकथन हैं कि अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए दो अन्य व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की गई थी जो रिक्त हो गए थे और दावा यह था कि केवल याचिकाकर्ता ही अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार था। पैरा 7 में पुनः शिकायत यह थी कि याचिकाकर्ता के अधीक्षक के रूप में पदोन्नत किए जाने के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाला गया था क्योंकि जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा विचार के लिए उसके नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। पैरा 8 में पुनः अभिकथन इस आशय के हैं कि याचिकाकर्ता चयन सूची या व्यक्तियों के पैनल में होने का हकदार था, जिन पर अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना था। इस संदर्भ में उन्होंने अनुलग्नक 'ए' के माध्यम से एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें फिर से कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता की ओर से किए गए दावे को अधीक्षक के उच्च पद पर पदोन्नत किया जाना था। इसी प्रकार, यह दावा करने वाला समान कथन कि पिछड़ा वर्ग के सदस्य के रूप में वह पद आदि पर अधिमान्य पदोन्नति का हकदार था, रिट याचिका के पैरा 11 में किया गया था और यहां तक कि प्रार्थना खंड में भी स्पष्ट रूप से दावा किया गया राहत यह है कि याचिकाकर्ता को उक्त पद पर पदोन्नत किया जाए।

(28) उपरोक्त से यह स्वतः स्पष्ट है कि वास्तव में याचिकाकर्ता की दलीलों में स्थापित एकमात्र मामला यह था कि वह अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने का हकदार था। यह वह मामला था जिसे पूरा करने के लिए उत्तरदाताओं को बुलाया गया था। मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ता के लिए यह अब कैसे खुला है कि वह अपनी दलीलों से पूरी तरह से भटक जाए और यह सुझाव देकर पूरी तरह पलटवार कर दे कि वह पदोन्नति के माध्यम से नहीं बल्कि किसी अन्य तरीके से पद का दावा करता है। अदालत में गंभीर कार्यवाही को लुभावनी चालों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, जिसमें एक पक्ष प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित और पूर्वाग्रहित करते हुए अपनी सुविधानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। वर्तमान संदर्भ में, मैं याचिकाकर्ता को उसकी दलीलों तक ही सीमित रखूंगा।

(29) यह भी ध्यान में रखना होगा कि राज्य सरकार के निर्देश, अनुलग्नक 'सी' और 'सी-1' मुख्य रूप से पदोन्नति के स्तर पर आरक्षण से संबंधित हैं। जहाँ तक प्रारंभिक भर्ती के चरण का संबंध है, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार दोनों की स्थिति समान है और टकराव का कोई संकेत नहीं है। निर्देशों का विचलन केवल पदोन्नति के स्तर पर आरक्षण के बिंदु पर होता है। यह इस संघर्ष के कारण था कि

एक बड़ी पीठ को यह संदर्भ आवश्यक हो गया था। यह 5 दिसंबर, 1972 के मेरे अकेले के निर्दिष्ट आदेश से अधिक स्पष्ट है । 15 अक्टूबर, 1974 के डिवीजन बेंच के निर्देश आदेश के संबंध में स्थिति फिर से समान है। इसमें यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि राज्य सरकार और इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के टकराव को देखते हुए इस प्रश्न का निर्धारण सुनिश्चित करना आवश्यक था कि क्या पिछड़े वर्गों के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के आरक्षण के संबंध में सरकारी निर्देश अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों पर भी एक बड़ी पीठ द्वारा लागू थे। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को अब यह तर्क देने की अनुमति देना कि पद पर याचिकाकर्ता का दावा पदोन्नति के माध्यम से नहीं है, इस संदर्भ के लिए आधार को नष्ट कर देगा। इस विचार पर भी, याचिकाकर्ता इस स्तर पर इस तरह का कोई विवाद उठाने के लिए तैयार नहीं है।

(30) इस तथ्य के अलावा कि यह तर्क याचिकाकर्ता के लिए खुला नहीं है, मैं अन्यथा स्पष्ट रूप से राय रखता हूं कि यहां मामला स्पष्ट रूप से पदोन्नति का है।

संबंधित नियमों में 'पदोन्नति' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिए, पदोन्नति की अवधारणा को यहां किसी विशिष्ट सेवा नियम या निर्देश की किसी भी परिभाषा के तहत नहीं बल्कि वास्तव में इसके व्यापक और सामान्य अर्थों में समझा जा रहा है। आधिकारिक वेबस्टर्स न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में दिए गए शब्द 'प्रोमोट' का शब्दकोश अर्थ इन शब्दों में दिया गया हैः-

"किसी अधिकारी को पदोन्नत करने के लिए पद, पद या सम्मान में उन्नति करना; ऊपर उठाना; प्राथमिकता देना; आगे बढ़ना; के रूप में"।

अब इस शब्द के सरल अर्थ को लागू करते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सहायक के पद से अधीक्षक के पद पर नियुक्ति, जो अब याचिकाकर्ता के पास है, निश्चित रूप से जिला न्यायाधीश के न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों के वर्ग के भीतर उसके लिए एक उच्च पद होगा। यह स्पष्ट रूप से स्थिति में वृद्धि और याचिकाकर्ता के लिए अग्रिम का संकेत देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधीक्षक के पद का वेतन क्लर्क और सहायकों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है। अन्यथा अधीक्षक के पद का तात्पर्य जिला न्यायाधीश की स्थापना में लिपिकों और सहायकों पर प्रशासनिक नियंत्रण और श्रेष्ठता का एक उपाय भी है। इस प्रकार साधारण शब्दकोश अर्थ का पालन करते हुए भी, याचिकाकर्ता का मामला स्पष्ट रूप से 'पदोन्नति' शब्द के दायरे में आएगा।

(31) सामान्य और सादे अर्थ को अलग कर दें तो स्थिति तब समान प्रतीत होती है जब शब्द की व्याख्या कला के सापेक्ष शब्द के रूप में की जाती है और आगे मिसाल का समर्थन किया जाता है। आधिकारिक कानून-शब्दावली में "शब्द और वाक्यांश." निम्नलिखित कहा गया है:--

"सिविल सेवा कर्मचारी को पदोन्नत करने का अर्थ है किसी ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को उच्च पद पर आगे बढ़ाना जो पहले निम्न डिग्री के कार्यालय में नियुक्त किया गया था।"

उपरोक्त निष्कर्ष मी आर्डल बनाम सिटी ऑफ शिकागो के निर्णय से लिया गया है (15)172 III एपीपी 142. कैम्पबेल बनाम पैट्रीज (16) 85 न्यूयॉर्क पूरक 853 में न्यायमूर्ति हूकर के निम्नलिखित शब्दों में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है :--

“इस धारा को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाए गए हैं (अध्याय 370, पृष्ठ 795, कानून 1899), और जांच, जहां तक इस मामले का संबंध है, इस सवाल पर खुद ही सुलझ जाती है कि क्या संबंधक का

विवरण या पदनाम था टेलीग्राफ ब्यूरो के सदस्य के रूप में पदोन्नति? यह प्रावधान किया गया है कि न्यूयॉर्क शहर के टेलीग्राफ ऑपरेटरों के पास रैंक होगा और वे पुलिस सार्जेंट का वेतन प्राप्त करेंगे। शब्द "पदोन्नति" इसे "उन्नति, या रैंक या सम्मान में ऊंचा उठाने का कार्य" के रूप में परिभाषित किया गया है; (वेबस्टर का डिक्ट.), और "उच्च पद, ग्रेड, वर्ग या पद पर उन्नति; सम्मान या गरिमा में प्राथमिकता." (मानक आदेश 1898)। न्यूयॉर्क शहर के पुलिस विभाग में एक गश्ती दल को $1,400 या उससे कम का वार्षिक मुआवजा मिलता है; जो लोग राउंडमैन के रूप में रैंक करते हैं उन्हें $1,400 और $1,500 के बीच का वार्षिक मुआवजा मिलता है; जबकि सार्जेंट के रूप में रैंक करने वालों को कम से कम $1,500 और न ही $2,000 से अधिक का वार्षिक मुआवजा मिलता है। पैट्रोलमैन और राउंडमैन कैप्टन के रूप में नियुक्ति के पात्र नहीं हैं। उन अधिकारियों का चयन सार्जेंटों की सूची से किया जाता है, या जो सार्जेंट के रूप में रैंक करते हैं, अर्थात् जासूस सार्जेंट और टेलीग्राफ ऑपरेटर। टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में रिलेटर, एक गश्ती दल के पदनाम को स्थायी करने का इरादा था, और इसलिए यह एक पदोन्नति थी, क्योंकि इसके साथ रैंक और वर्ग में उन्नति के साथ-साथ उसे प्राप्त होने वाले वेतन में भी उन्नति होती थी।"

(32) मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि प्रासंगिक नियमों के तहत, अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए प्रदान किया गया तरीका पदोन्नति के माध्यम से एक है और पहली नियुक्ति के माध्यम से नहीं है।

(34) श्री सेठी के प्रति निष्पक्षता में, मुझे ध्यान देना चाहिए कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के तर्क का खंडन करने के लिए कि वर्तमान मामला पहली नियुक्ति में से एक था, उन्होंने दृढ़ रुख अपनाया था कि यहां तक कि पहली नियुक्ति भी नहीं होगी अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े विभिन्न पदाधिकारियों के पद संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की पूर्णता के दायरे में आ सकते हैं। हालाँकि, जैसा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अधीक्षक के पद पर नियुक्ति का तरीका स्पष्ट रूप से पदोन्नति के माध्यम से है, इस संदर्भ में प्रतिवादी की ओर से विवाद की जांच करना अनावश्यक है क्योंकि सख्ती से यह उत्पन्न नहीं होता है।

(34) जटिल कानूनी प्रश्न का उत्तर दिए जाने के बाद, राज्य के निर्देशों की प्रयोज्यता या अन्यथा के बारे में विशिष्ट मुद्दा, याचिकाकर्ता के मामले में अनुलग्नक 'सी' और 'सी-1', संबंधित मामले के साथ खुद को हल करता है। संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर, उच्च न्यायालय को जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों और मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों पर नियंत्रण प्राप्त है। इस नियंत्रण में ऐसे सभी पदाधिकारियों को पदोन्नति की शक्ति शामिल है। केवल उच्च न्यायालय ही सबसे अच्छा न्यायाधीश है कि इनमें से कौन से पदाधिकारी और अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय कर्मचारी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त या योग्य हैं। इसलिए इस संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय में निहित होगी। यह उच्च न्यायालय के प्रांत के भीतर होने के कारण, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा उस पर कोई भी हस्तक्षेप विशेष रूप से उसे दिए गए नियंत्रण के क्षेत्र में घुसपैठ होगी और इसलिए, अनुचित होगी। असम राज्य और एक अन्य बनाम एस. एन. सेन और एक अन्य (17) A.I.R. 1972 S.C. 1028 में यह प्राधिकृत रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन विशेष रूप से उच्च न्यायालय में निहित है और इसलिए

राज्य सरकार द्वारा इस आशय का नियम बनाया गया है कि अधीनस्थ न्यायाधीशों की पुष्टि राज्यपाल द्वारा की जाएगी, जिसे असंवैधानिक के रूप में निरस्त कर दिया गया था। अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों के संबंध में मामले का अनुपात जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होता है। यदि अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों की पदोन्नति और यहां तक कि उनकी पुष्टि भी पूरी तरह से उच्च न्यायालय के नियंत्रण में है, तो यह इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायालय के पदाधिकारियों की पदोन्नति और पुष्टि भी समान आधार पर होनी चाहिए। नतीजतन, इन पदाधिकारियों की पदोन्नति का क्षेत्र पूरी तरह से और विशेष रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण के क्षेत्र के भीतर है और संविधान के प्रावधानों को देखते हुए इसमें कोई भी घुसपैठ अनुचित होगी। राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में बनाए गए कोई भी निर्देश या नियम, इसलिए, अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उनका एकमात्र नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। इस मामले को दो कोणों से देखा जा सकता है। एक दृष्टिकोण से देखने पर यह या तो कहा जा सकता है कि ऐसे निर्देशों का आशय वास्तव में केवल राज्य के उन सिविल सेवकों पर लागू होना है जो सीधे उसके नियंत्रण में हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों पर नहीं जिनका नियंत्रण स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है। किसी भी मामले में यदि ऐसा कोई निर्देश विशेष रूप से उच्च न्यायालय के नियंत्रण के भीतर कार्य करने वालों पर थोपा जाना चाहा जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा निहित उच्च न्यायालय के अनन्य नियंत्रण पर प्रभाव डालने के समान होगा और इसलिए असंवैधानिक होगा।

(35) कुछ दोहराव की कीमत पर, मामले को संक्षेप में एक शब्दांश में रखा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के पदाधिकारियों का नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। यह नियंत्रण अपने दायरे में राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को बाहर रखते हुए पदोन्नति की शक्ति की परिकल्पना करता है। इसलिए, इस संदर्भ में राज्य द्वारा जारी कोई भी निर्देश ऐसे पदाधिकारियों पर लागू नहीं होता है और अकेले उच्च न्यायालय ही ऐसे निर्देश जारी करने में सक्षम है।

(36) इस प्रकार रिट याचिका को निराधार पाया गया और खारिज कर दिया गया। यहां उठने वाले कानून के पेचीदा सवाल को देखते हुए, मैं पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ता हूं।

न्यायमुर्ति मित्तल, - मैं सहमत हूं।

न्यायमुर्ति मन मोहन सिंह गुजराल ।

(37) मुझे संधावालिया, न्यायमुर्ति के फैसले को पढ़ने का लाभ मिला है। लेकिन अपने विद्वान भाई के प्रति पूरे सम्मान के साथ, मैं अपने आप को यह समझाने में सक्षम नहीं हो सका कि संविधान के अनुच्छेद 235 और जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के क्लर्कों (अब अधीक्षकों) की नियुक्ति और नियंत्रण से संबंधित नियमों की व्याख्या को प्रासंगिक नियमों की भाषा में हिंसा किए बिना और अनुच्छेद 235 के प्रावधान के महत्व और प्रभाव को नजरअंदाज किए बिना और 23 जून, 1937 और 18 जुलाई, 1939 की पंजाब सरकार की अधिसूचनाओं, जिसके तहत प्रासंगिक नियम बनाए गए थे, तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए, मैंने एक अलग निर्णय लिखना आवश्यक पाया है।

(38) इस याचिका के निर्णय के लिए आवश्यक तथ्य विवाद में नहीं हैं और एक संकीर्ण दायरे में हैं। याचिकाकर्ता वर्तमान में अमृतसर के वरिष्ठ अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में क्लर्क के रूप में कार्यरत है और न केवल पिछड़े वर्ग से है बल्कि स्नातक भी है। न्यायालय के क्लर्क (अब अधीक्षक) का पद (बाद

में अधीक्षक के पद के रूप में संदर्भित) रिक्त होने के कारण, इस पद के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अमृतसर द्वारा सिफारिशें की गईं। यह पता चलने पर कि इस पद के लिए सिफारिश करने में उनकी उपेक्षा की गई है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यालय में कार्यरत दो अन्य सहायकों के नाम भेजे गए हैं, याचिकाकर्ता ने रजिस्ट्रार के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक अभ्यावेदन दिया और प्रार्थना की कि उनका नाम उन व्यक्तियों के पैनल में शामिल किया जाना चाहिए जिन पर अधीक्षक के पद के लिए विचार किया जाना था। इस अभ्यावेदन को खारिज कर दिया गया था और इस अस्वीकृति के बारे में याचिकाकर्ता को जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा 16 फरवरी, 1971 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था। पहले के अभ्यावेदन से संतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने 20 फरवरी, 1971 को एक अन्य अभ्यावेदन के माध्यम से फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उस अभ्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी, क्योंकि उस पर कार्रवाई के दौरान, वर्तमान याचिका मार्च, 1971 में दायर की गई थी।

(39) जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा वरिष्ठता और उच्च शैक्षिक योग्यता के आधार पर सिफारिश किए गए सम्पूरण सिंह और मान सिंह पर वरीयता के लिए अपने दावे को आधार बनाने के अलावा, याचिकाकर्ता ने अपना दावा मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर आधारित किया। इन निर्देशों की प्रतियों को अभिलेख पर रखा गया है और उन्हें अनुलग्नक सी और सी1 के रूप में चिह्नित किया गया है। इन निर्देशों के बल पर याचिका में यह दावा किया गया है कि पिछड़ा वर्ग का सदस्य होने के नाते उसे अन्य अधिकारियों की वरीयता में चुना जाना था, क्योंकि ये निर्देश याचिकाकर्ता के मामले को नियंत्रित करते हैं और जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक के पद के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किए जाने वाले चयन के मामले से पूरी तरह से आकर्षित होते हैं।

(40) रजिस्ट्रार द्वारा दायर हलफनामों के माध्यम से प्रतिवादियों की ओर से याचिका का विरोध किया जाता है। पहला हलफनामा 7 जनवरी, 1972 का है और इसे मुख्य याचिका के जवाब में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्रतिकृति के जवाब में दूसरा हलफनामा 27 मई, 1972 को दायर किया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता पर लागू नियमों का प्रश्न स्पष्ट नहीं था, इसलिए 12 सितंबर, 1975 को उप-पंजीयक (नियम) श्री लोबाना द्वारा एक और हलफनामा दायर किया गया था।

(41) इन शपथपत्रों में याचिकाकर्ता द्वारा स्थापित तथ्यात्मक स्थिति का विरोध नहीं किया गया है और यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता की उपेक्षा करने का कारण यह है कि उसे जिला और सत्र न्यायाधीश द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था, क्योंकि नागरिक और आपराधिक कानून के बारे में उसका ज्ञान पर्याप्त नहीं माना गया था। यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता का मामला पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों के दायरे में नहीं आता है। 27 मई, 1972 के हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया गया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा 20 नवंबर, 1969 को जारी किए गए निर्देश वास्तव में याचिकाकर्ता के मामले में लागू थे और इन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पदों का आरक्षण केवल प्रारंभिक भर्ती के मामले में ही किया जा सकता था, न कि पदोन्नति के समय। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अधीक्षक का पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है न कि भर्ती और आरक्षण द्वारा, इसलिए उच्च न्यायालय के परिपत्र पत्र के संदर्भ में दावा नहीं किया जा सकता है और आगे कहा जा सकता है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में अनुलग्नक सी और सी 1 के माध्यम से सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश अधीक्षक के पद सहित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठान पर लागू नहीं थे।

अनुच्छेद 235 और न्यायालय के लिपिकों (अब अधीक्षकों) की नियुक्ति और नियंत्रण से लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तक के नियमों तक पहुंचा जा सकता है। प्रासंगिक नियमों की भाषा में हिंसा और संविधान के अनुच्छेद 235

(42) इसलिए, दोनों पक्षों द्वारा अपनाया गया अड़ियल रुख निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का दावा करता है:--

(1) क्या अनुच्छेद 235 में परिकल्पित उच्च न्यायालय का नियंत्रण जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में काम करने वाले सभी पदाधिकारियों तक फैला हुआ है इसके अलावा और क्या यह नियंत्रण सरकार को उस आधार पर नियम बनाने या निर्देश जारी करने से रोक देगा जिसके आधार पर जिला और पुलिस अधीक्षक का पद नियुक्त किया जा सकता है। सेशन जज को भरा जाना है?

(2) क्या जिला एवं जिला अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की गयी है? सेशन जज प्रमोशन से भरा जाता है या भर्ती से?

(3) यदि यह माना जाता है कि ये पद पदोन्नति से भरे गए हैं, तो क्या अनुबंध सी और सी-एल में निहित निर्देश लागू होंगे या उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे? दूसरी ओर, यदि निष्कर्ष यह है कि ये पद भर्ती द्वारा भरे गए हैं, तो निर्देशों के दो सेटों में से कौन सा आकर्षित होगा?

(43) विभिन्न कोणों से समस्या की जांच करने का कार्य शुरू करने से पहले, जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक की नियुक्ति के लिए लागू नियमों का उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करना उपयोगी होगा। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधिनियमन से पहले, जिला और सत्र न्यायाधीशों के अधीक्षकों की नियुक्ति पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1908 की धारा 35 द्वारा शासित थी और नियम उच्च न्यायालय द्वारा धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत बनाए गए थे। ये नियम अध्याय 18-ए, खंड I, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में निहित हैं। इस अधिनियम की धारा 241 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन भारत सरकार अधिनियम, 1935 के प्रवृत्त होने के पश्चात् राज्यपाल या उसके नामनिर्देशित में निहित प्रांत के मामलों के संबंध में सिविल सेवा और पदों पर नियुक्तियां करने की शक्ति और उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल किसी प्रांत के मामलों के संबंध में सेवारत व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता था। हालाँकि पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 35 को भारत सरकार (भारतीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा निरसित किया गया था, लेकिन अध्याय 18-क खंड 1, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में निहित नियमों को इस आदेश के अनुच्छेद 10 द्वारा तब तक सुरक्षित रखा गया था जब तक कि इस संबंध में अन्य प्रावधान सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किए गए थे।

(44) भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल ने 23 जून, 1937 को निम्नलिखित अधिसूचना जारी की:--

"भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब के राज्यपाल ने प्रांत के न्यायिक विभाग में नियुक्तियां करने और उस विभाग में महामहिम की सेवा करने वाले व्यक्तियों के लिए सेवा की शर्तें निर्धारित करने के लिए अपने अधिकार के निम्नलिखित प्रतिनिधिमंडल बनाए हैं। नई नियुक्तियां सृजित करने के लिए यहां प्रत्यायोजित शक्तियां

इस परंतुक के अधीन हैं कि उनका प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि वे प्रांतीय बजट के सुसंगत उपबंधों को और वित्तीय शक्तियों की पुस्तक के पैराग्राफ 20.3 और 19.9 के उपबंधों को पार कर जाएँः –

विलोपन

प्रतिनिधिमंडल की क्रमिक प्रकृति नं.	किसे सौंपा गया	विस्तार
1. लाहौर में उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की मंत्रिस्तरीय स्थापना और उन न्यायालयों में प्रक्रिया सर्वर की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले नियम बनाना।	लाहौर में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश	इन शर्तों के अधीन पूर्ण शक्तियां कि नियमों के लिए प्रांतीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी
2. उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठानों के पदों पर नियुक्तियां करना और सर्वरों को संसाधित करना।	जिला और सत्र न्यायाधीश	पूर्ण शक्तियाँ।

* * *

उपरोक्त अधिसूचना को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की मंत्रिस्तरीय स्थापना की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने वाले नियम बनाने की शक्ति दी गई थी जिसमें जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक शामिल होंगे। . हालाँकि, अधीक्षक सहित मंत्रिस्तरीय स्थापना की नियुक्ति जिला और सत्र न्यायाधीश पर छोड़ दी गई थी। इन नियमों को बनाने में उच्च न्यायालय और इन नियुक्तियों को करने में जिला और सत्र न्यायाधीशों को राज्यपाल के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना था। उपरोक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय ने जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय अधीक्षकों की नियुक्ति और नियंत्रण से संबंधित नियम बनाए। इन नियमों को सरकार की मंजूरी के बारे में 21 नवंबर, 1940 के पत्र द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया था। भारत सरकार के अनुच्छेद 10 के आधार पर (भारतीय कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 1937, इन नियमों ने अध्याय 18-ए, खंड 1, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों में निहित पहले के नियमों को हटा दिया, जहां तक अधीक्षकों की नियुक्ति का संबंध था, क्योंकि पहले के नियम केवल बने रहने थे यह तब तक लागू रहेगा जब तक कि संबंधित मामले को विनियमित करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कोई अन्य प्रावधान नहीं किया जाता। इन नियमों को सरकार की मंजूरी मिलने से पहले पंजाब के राज्यपाल ने 23 जून, 1937 की अधिसूचना में 18 जुलाई, 1939 की अधिसूचना संख्या 4654-जे-39/23984 द्वारा संशोधन किया, जिससे नियुक्तियां करने की शक्ति मिल गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के अधीक्षक का पद जिला एवं सत्र न्यायाधीशों से छीनकर उच्च न्यायालय को दे दिया गया। पिछली अधिसूचना में परिणामी परिवर्तन किए गए, जिसके परिणामस्वरूप जहां तक जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक की नियुक्ति का संबंध था, उच्च न्यायालय राज्यपाल का प्रतिनिधि बन गया।

(45) इस स्तर पर अधीक्षक को नियंत्रित करने वाले नियमों को व्यापक रूप से निर्धारित करना उपयोगी होगा, क्योंकि बाद में इन नियमों का संदर्भ देना होगा।

"जिला एवं सत्र न्यायालय के लिपिकों (अधीक्षक) की नियुक्ति एवं नियंत्रण से संबंधित नियम न्यायाधीशों को सिविल में शामिल किया जाएगा न्यायालय स्थापना (नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियम (जून, 1947 तक संशोधित)।

1. न्यायालय से लेकर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के क्लर्कों के पदों को चयन पदों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और प्रांतीय कैडर पर होगा।

2. नियुक्ति करने में सक्षम प्राधिकारी:-- जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के क्लर्क के पद पर नियुक्ति, चाहे स्थायी हो या स्थानापन्न, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी:

बशर्ते कि संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा पुष्टि के अधीन, तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए अवकाश रिक्ति में सी.ओ.सी. के पद पर स्थानापन्न नियुक्ति कर सकते हैं।

3. उम्मीदवारों का नामांकन:-- जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय के क्लर्क के रूप में नियुक्ति के लिए स्वीकृत उम्मीदवारों की एक सूची उच्च न्यायालय द्वारा रखी जाएगी। इस सूची में केवल उतने ही उम्मीदवार शामिल होंगे जितने दो या तीन वर्षों के भीतर शामिल किए जा सकें। सूची गोपनीय होगी और किसी भी व्यक्ति को यह सूचित करना आवश्यक नहीं होगा कि उसका नाम इसमें जोड़ा गया है या हटा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करने पर विचार करने से पहले उसे निम्नलिखित शर्तों में एक घोषणा पर हस्ताक्षर करना होगा:--

"यदि जिला एवं सत्र न्यायाधीश का सी.ओ.सी. नियुक्त किया जाता है तो मैं पंजाब में कहीं भी तैनात होने के लिए तैयार रहूंगा और मैं मानता हूं कि यदि मैं स्थानांतरण के खिलाफ विरोध करूंगा, तो मैं अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।"

4. योग्यता:-- जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सी.ओ.सी. के पद पर नियुक्ति केवल नियम 3 के तहत स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची में से की जाएगी। इन उम्मीदवारों का चयन अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों में से चयन द्वारा किया जाएगा। 50% मुस्लिम, 30% हिंदू और अन्य और 20% सिखों का अनुपात।

5. सेवा की शर्तें:-- जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालय के क्लर्क उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के आदेशों के तहत पंजाब के भीतर एक सत्र प्रभाग से दूसरे में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होंगे।

6. दंड:--

(i) अनुशासन, दंड और अपील से संबंधित मामलों में जिला और सत्र न्यायाधीश को सी. ओ. सी. पंजाब अधीनस्थ सेवा (दंड और अपील) नियम, 1930 या ऐसे अन्य नियमों के अधीन होगा, जो पंजाब सरकार इसके पश्चात् इस निमित्त बनाएगी और पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 की धारा 36 के अधीन जुर्माने की सजा के अधीन भी होगी।

(ii) एक जिला और सत्र न्यायाधीश अपने सी.ओ.सी. पर जुर्माना, निंदा या वेतन वृद्धि रोकने की सजा दे सकता है। अन्य सभी दंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के आदेश द्वारा लगाए जाएंगे। इस

संबंध में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों का आदेश उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्य के प्रभारी न्यायाधीश द्वारा पारित किया जाएगा।

7. अपील:--

(i) जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उसके सीओसी पर कोई जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के समक्ष अपील की जाएगी। माननीय न्यायाधीशों के आदेश न्यायाधीश द्वारा पारित किए जाएंगे उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्य के प्रभारी।

(ii) न्यायालय के प्रशासनिक कार्य के प्रभारी न्यायाधीश के सीओसी पर कोई जुर्माना लगाने के आदेश के खिलाफ जिला अंत सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में की जाएगी।''

(46) इस मामले में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाले बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का नियंत्रण जिला न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में काम करने वाले सभी अधिकारियों तक फैला हुआ है। मोहम्मद गौस बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (4) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 235 में आने वाले "न्यायालय" शब्द में न केवल जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, बल्कि इन न्यायालयों के सभी पदाधिकारी और उनसे संबंधित मामले भी शामिल हैं। इस विचार का अनुसरण नृपेंद्र नाथ बागची बनाम पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव (5) मामले में पूर्ण पीठ ने भी किया था और इसलिए यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि अनुच्छेद 235 द्वारा परिकल्पित उच्च न्यायालय का नियंत्रण न केवल पीठासीन अधिकारियों के लिए है, बल्कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े पदाधिकारियों और मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों के लिए भी है।

(47) समस्या का दूसरा चरण जिला और सत्र न्यायाधीशों के अधीक्षकों की नियुक्ति के लिए उनके नियम बनाने से संबंधित है। हालाँकि ये नियम उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए थे, लेकिन यह राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 जून, 1937 की अधिसूचना के माध्यम से उन्हें प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर किया गया था, क्योंकि इन नियमों को बनाने की शक्ति राज्यपाल या उनके मनोनीत व्यक्ति में निहित थी। इन नियमों को बनाने में उच्च न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 की उप-धारा (2) (बी) के तहत राज्यपाल के मनोनीत व्यक्ति के रूप में कार्य किया। अन्यथा भी भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन, धारा 241 की उपधारा (1) (ख) के अधीन राज्यपाल में निहित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय प्रतिष्ठानों की नियुक्तियाँ और उच्च न्यायालय स्वयं इन नियुक्तियों को या तो नहीं कर सकता था या ऐसे नियम नहीं बना सकता था जिनके अधीन ये नियुक्तियाँ की जा सकें।

(48) विचार को पूरा करने के लिए, पहला प्रश्न यह देखा जाना चाहिए कि भारत के संविधान के लागू होने से स्थिति में क्या परिवर्तन, यदि कोई हो, लाया गया है। जहां तक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों की नियुक्ति का सवाल है, संविधान में कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है और अनुच्छेद 309, 310 और 311 इन नियुक्तियों पर भी लागू होंगे। अधीक्षकों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विधायिका के उचित अधिनियम द्वारा या, यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो राज्यपाल या ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा, जैसा वह निर्देश दे, विनियमित किया जा सकता है। चूंकि अभी तक राज्य विधानमंडल या राज्यपाल या उनके नामित व्यक्ति द्वारा कोई

नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए अनुच्छेद 310 के प्रावधान के तहत उच्च द्वारा बनाए गए नियम हैं। चूंकि राज्य विधानमंडल या राज्यपाल या उनके नामनिर्देशित द्वारा अब तक कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, इसलिए अनुच्छेद 310 के परन्तुक के तहत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 (2) (ख) द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण के तहत उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम लागू रहेंगे, क्योंकि ये नियम संविधान के अनुच्छेद 372 द्वारा सहेजे गए हैं। हालाँकि, इन नियमों को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के सहायक कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के दूसरे सेट द्वारा प्रतिस्थापित करने की शक्ति राज्य विधानमंडल और राज्यपाल में निहित है। इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता है कि कार्यकारी निर्देशों द्वारा राज्यपाल 1940 में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को जोड़ या संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के नामित व्यक्ति के रूप में बनाए गए थे। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही नियम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए हों, कार्यकारी निर्देश उस क्षेत्र को कवर करने के लिए जारी किए जा सकते हैं जो विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत नहीं आता है।1940 में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के मामले में, इन्हें उच्च न्यायालय द्वारा राज्यपाल के मनोनीत के रूप में बनाए जाने के बाद, राज्यपाल के कार्यकारी निर्देशों द्वारा बदला या संशोधित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 235 में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो किसी भी तरह से जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक के पद सहित उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने के राज्यपाल के अधिकार को छीन लेता है।

(49) प्रतिवादी की ओर से उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक का पद पदोन्नति से भरा जाता है, भर्ती से नहीं और इसलिए, ये नियुक्तियाँ उच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आती हैं। , जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 235 में परिकल्पित नियंत्रण का विस्तार जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों और उनके मंत्रालयिक कर्मचारियों की पदोन्नति तक है। मामले का यह पहलू जैसा कि दूसरे प्रश्न में शामिल है और इसका उत्तर 1940 में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों की व्याख्या पर निर्भर करेगा जिसके तहत नियुक्तियां की जाती हैं और वह प्राधिकारी जिसके तहत ये नियम बनाए गए थे। नियमों के शीर्षक में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ये अधीक्षकों की नियुक्ति और नियंत्रण से संबंधित हैं। नियम 2 उस तरीके को प्रदान करता है जिसमें ऐसी नियुक्तियाँ की जानी हैं और यह कहा गया है कि, चाहे नियुक्तियाँ स्थायी हों या स्थानापन्न, ये उच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती हैं। नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए स्वीकृत उम्मीदवारों की सूची से की जानी है और इस सूची के उम्मीदवारों का चयन अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत लिपिक कर्मचारियों में से किया जाना है। नियम 4, जो योग्यता से संबंधित है, उस पद्धति का प्रावधान करता है, जिसके द्वारा सूची तैयार की जानी है। अधीक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नियम 6 के तहत की जा सकती है और इस नियम के अनुसार, पंजाब अधीनस्थ सेवा (दंड और अपील) नियम, 1930, उनके मामले में लागू होते हैं।

(50)नियमों की उपरोक्त चर्चा से यह पता चलेगा कि यद्यपि अधीक्षणों के पदों के लिए चयन अधीनस्थ न्यायालयों में नियोजित लिपिक कर्मचारियों तक ही सीमित है, लेकिन ये पद नियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं न कि पदोन्नति द्वारा और ये पद प्रांतीय संवर्ग में हैं जबकि अन्य पद जिला संवर्ग में हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में काम करने वाले क्लर्क के लिए अधीक्षक के रूप में नियुक्ति जीवन में इस अर्थ में पदोन्नति के बराबर होगी कि उसके पास बेहतर स्थिति और परिलब्धियां होंगी, लेकिन यह उस अर्थ में पदोन्नति के बराबर नहीं होगा जिसमें अनुच्छेद 235 में अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। यह तर्क कि चूंकि भर्ती अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों तक सीमित है और खुली प्रतिस्पर्धा या

खुले बाजार से नहीं है, इसलिए इन नियुक्तियों को केवल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली पदोन्नति का मामला नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि भर्ती का स्रोत यह निर्धारित करने के लिए एकमात्र परीक्षा नहीं है कि क्या किसी पद को भरना अनुच्छेद 235 के अर्थ के भीतर पदोन्नति के बराबर है या अनुच्छेद 235 के दायरे से बाहर की नियुक्ति है। कुछ अन्य प्रासंगिक विचार यह हैं कि क्या जिस पद पर नियुक्ति की जानी है, वह उसी संवर्ग से है जिसमें से चयन किया जाना है या एक अलग संवर्ग से है, क्या दोनों पद भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में समान नियमों द्वारा शासित हैं, क्या दोनों मामलों में नियुक्ति प्राधिकरण समान है या अलग है, क्या पद एक ही वेतनमान या अलग-अलग वेतनमान में आते हैं और क्या नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नियम इस नियुक्ति को भर्ती या पदोन्नति के रूप में मानते हैं। इसके अलावा, पदोन्नति आमतौर पर यह दर्शाती है कि जिन व्यक्तियों में से चयन किया जाना है, वे एक संवर्ग के सदस्य हैं जिनकी अंतर वरिष्ठता है। पदोन्नति के मामले में चयनात्मक प्रक्रिया आम तौर पर वरिष्ठता पर विचार करने तक सीमित होती है, यदि अन्यथा वरिष्ठ पदधारी उस पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए उपयुक्त है जिस पर पदोन्नति की जानी है। दूसरी ओर, यदि जिन व्यक्तियों में से चयन किया जाना है, वे विभिन्न संवर्गों के सदस्य हैं जिनकी कोई अंतर वरिष्ठता नहीं है, तो यह कनिष्ठ संवर्ग से पदोन्नति का मामला नहीं होगा, बल्कि प्रारंभिक नियुक्ति या भर्ती का मामला होगा। नियुक्ति के मामले में चयन का तत्व एक प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि चयन विभिन्न विचारों के आधार पर किया जाता है, जिसमें शैक्षिक योग्यता, सेवा का पिछला रिकॉर्ड और अनुभव, यदि कोई हो, सामान्य स्तर की बुद्धिमत्ता और किसी पद के लिए उपयुक्तता, शैक्षणिक कैरियर और विशेष या उच्च योग्यता, यदि कोई हो। उपर्युक्त दृष्टिकोण को लेते हुए मुझे सत्य कुमार और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (8) मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय से समर्थन मिलता है, जिसमें यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि क्या अनुच्छेद 234 किसी राज्य की न्यायिक सेवा में पहली नियुक्ति या बाद की पदोन्नति पर भी लागू होता है और इस संदर्भ में "पदोन्नति" शब्द के वास्तविक महत्व पर विचार किया गया था। यह निर्णय दिया गया था कि 'चयन' शब्द में योग्यता और क्षमता पर विचार करना शामिल है, न कि केवल वरिष्ठता पर, 'पदोन्नति' शब्द का अर्थ आमतौर पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति होगा, जब तक कि निश्चित रूप से अधिकारी का रिकॉर्ड पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए बहुत खराब न हो।

(51) ऊपर उल्लिखित दृष्टिकोण से अधीक्षक की स्थिति की जांच करने पर, यह सामने आएगा कि जिस लिपिक कर्मचारी का चयन किया जाना है वह विभिन्न संवर्गों से संबंधित है, क्योंकि प्रासंगिक नियमों के तहत एक अलग संवर्ग होना चाहिए जहां तक जिला और सत्र न्यायाधीश की मंत्रिस्तरीय स्थापना का संबंध है, प्रत्येक राजस्व जिले और प्रत्येक लघु वाद न्यायालय के लिए एक अलग कैडर। एक जिले के एक क्लर्क की दूसरे जिले के उसके समकक्ष के साथ कोई पारस्परिक वरिष्ठता नहीं होती है और उच्च न्यायालय द्वारा रखी गई चयनित उम्मीदवारों की सूची में नामों को वरिष्ठता के किसी भी क्रम में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, अधीक्षकों की नियुक्ति नियमों के अलग-अलग सेट द्वारा शासित होती है और नियुक्ति प्राधिकारी उस प्राधिकारी से अलग होता है जो जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के अन्य मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। यहां तक कि अधीक्षकों से संबंधित नियम भी उनके चयन को नियुक्ति मानते हैं, क्योंकि नियम 2 नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी की बात करता है और शीर्षक से पता चलता है कि ये नियम अधीक्षकों की नियुक्ति और नियंत्रण से संबंधित हैं। इसके अलावा, 18 जुलाई, 1939 की अधिसूचना, जिसके तहत 23 जून, 1937 की पिछली अधिसूचना को संशोधित किया गया था, यह दर्शाती है कि अधीक्षकों की नियुक्ति करने की शक्ति जो पंजाब के राज्यपाल में निहित थी, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सौंप दिया गया था और इसमें सम्मान करते हुए उच्च न्यायालय

को पूर्ण अधिकार दिये गये। यदि यह पदोन्नति का मामला होता तो इस अधिसूचना में इसका उल्लेख होता और नियमों में इसे विभिन्न सत्र प्रभागों में कार्यरत लिपिकों की पदोन्नति माना जाता। मामले को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अध्याय 18-ए में निहित नियमों की तुलना के माध्यम से जांच करना प्रासंगिक होगा जो अधीक्षक के पद को छोड़कर जिला और सत्र न्यायाधीशों की मंत्रिस्तरीय और सहायक स्थापना से संबंधित हैं। इन नियमों से यह प्रतीत होता है कि पहले नियुक्तियाँ सामान्यतः निम्नतम स्तर पर की जाती हैं और मंत्रिस्तरीय स्थापना के उच्च ग्रेडों पर नियुक्ति सामान्यतः निम्न ग्रेडों से पदोन्नति द्वारा की जाती हैं। यह नियम 6 में प्रदान किया गया है। यह नियम आगे वह विधि प्रदान करता है जिसके द्वारा उच्च ग्रेड में स्थायी रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरा जाना है। एक जिले के सभी मंत्रालयिक अधिकारियों को एक संयुक्त कैडर माना जाता है, लेकिन कैडर को दो ग्रेड, निम्न ग्रेड और उच्च ग्रेड में प्रदान किया जाता है। जैसा कि पहले देखा गया है, उच्च ग्रेड के पद निचले ग्रेड के पदों से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं, न कि नई भर्ती से। अधीक्षक का पद संयुक्त संवर्ग में शामिल नहीं है और इसे एक अलग संवर्ग माना जाता है।

(52) अतः उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा कि मामले को जिस भी दृष्टिकोण से देखा जाए, जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक का पद नियुक्ति द्वारा भरा जाता है, न कि पदोन्नति द्वारा और इन पदों को भरने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है, न कि अनुच्छेद 235 के तहत नियंत्रण की शक्ति के कारण, बल्कि 23 जून, 1937 और 18 जुलाई, 1939 की अधिसूचनाओं के तहत राज्यपाल द्वारा उसे सौंपी गई शक्ति के कारण। इस मामले का एक और पहलू भी है। यदि अधीक्षणकों के पदों पर नियुक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 235 के आधार पर उसमें निहित नियंत्रण की शक्ति के कारण उच्च न्यायालय के दायरे में आने वाली पदोन्नति के रूप में माना जाता है, तो राज्यपाल के लिए इन नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाने या इन नियुक्तियों को करने के लिए उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करने का कोई अवसर नहीं था और इसके अलावा उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के लिए सरकार से अनुमोदन लेने का कोई अवसर नहीं होता, क्योंकि केवल उच्च न्यायालय ही अधीनस्थ लिपिक कर्मचारियों से नियम बनाने या पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियां करने के लिए सक्षम होता। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण पूर्ण और निरंकुश होने के कारण, केवल उच्च न्यायालय ही नियम बना सकता था और इस शक्ति के आधार पर नियुक्तियां कर सकता था और राज्यपाल की नियम बनाने या नियुक्तियां करने की शक्ति से यह शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी।

(53) अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की शक्तियों में प्रत्यक्ष संघर्ष, जिसमें पदोन्नति करने की शक्ति और जिला और सत्र न्यायाधीशों के अधीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियम बनाने के लिए राज्य विधानमंडल या राज्यपाल का अधिकार शामिल है, का भी समाधान किया जा सकता है यदि मामले को किसी अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहम्मद सुजात ए. यू. और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (18) 1974 (2) S.L.R. 508. मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार सेवा की शर्त है और वह नियम जो वास्तविक पदोन्नति के अधिकार या पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से संबंधित है, सेवा की शर्तों को विहित करने वाला नियम है। इसलिए, यह माना जाएगा कि पदोन्नति से संबंधित नियम भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम हैं। इसलिए इन नियमों का निर्माण अनुच्छेद 309 के दायरे में आएगा। जहां तक ये नियम पदोन्नति से संबंधित हैं, इन नियमों का वास्तविक कार्यकरण अनुच्छेद 235 के आधार पर उच्च न्यायालय की शक्तियों के भीतर आएगा और यह केवल उच्च न्यायालय है जो उन नियमों को संचालित कर सकता है और उन्हें व्यक्तिगत मामलों में लागू कर सकता है। जैसा कि किसी भी राज्य के

मामलों के संबंध में अन्य सेवाओं या पदों के मामलों में सरकार नियम बना सकती है या निर्देश जारी कर सकती है, इसलिए अधीक्षकों के पदों के मामले में नियम राज्य विधानमंडल या राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 309 के संदर्भ में बनाए जा सकते हैं और ऐसे मामलों में भी राज्यपाल द्वारा निर्देश जारी किए जा सकते हैं जहां नियम मौन हैं। जहां तक अधीक्षकों के पदों को भरने के मामले का संबंध है, व्यक्तिगत मामलों में इन नियमों के प्रभावी संचालन को उच्च न्यायालय पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें अनुच्छेद 235 के आधार पर नियंत्रण की शक्ति निहित है।

(54) अनुच्छेद 235 का उपबंध स्पष्ट रूप से इस बात पर प्रकाश डालता है कि जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का जो अधिकार नियंत्रण है, वह जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों की अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों और उन न्यायालयों के पदाधिकारियों को भी नियंत्रित करने वाली सेवा की शर्तों के संबंध में किसी भी कानून के अधीन है। आवश्यक निष्कर्ष यह है कि पदोन्नति के मामलों में भी जो नियंत्रण के दायरे में आते हैं, उच्च न्यायालय को जिला न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत निर्धारित सेवा की शर्तों के अनुसार आगे बढ़ना है। "सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाला कानून" शब्द उन नियमों को संदर्भित करता है जो इस अनुच्छेद में उल्लिखित विभिन्न पदों के अधिकारियों को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों को बनाने या कानून को निर्धारित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस संदर्भ में संदर्भ जिला न्यायाधीशों के अलावा किसी अन्य राज्य की न्यायिक सेवा के संबंध में अनुच्छेद 234 के तहत बनाए गए नियमों और अध्याय XIV द्वारा कवर की गई सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों के लिए है। जब तक अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित किसी व्यक्ति के नियंत्रण की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाली कोई कानून है, तब तक उच्च न्यायालय उस कानून के अनुसार नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए बाध्य है न कि उस कानून की अवहेलना में। सत्य कुमार के मामले (उपर्युक्त) में इसी प्रकार के प्रश्न की जांच की गई थी, जिसमें अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय के नियंत्रण के प्रश्न पर निम्नलिखित शब्दों में विचार किया गया थाः-

"जबकि अनुच्छेद 235 में निर्दिष्ट नियम हालांकि अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल द्वारा बनाए जाने हैं, उक्त नियम लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। वह नियंत्रण जो अनुच्छेद 235 के अधीन उच्च न्यायालय में निहित है और जिसमें पदोन्नति सम्मिलित है, इस शर्त के अधीन बनाया गया है कि वह इस प्रकार उच्च न्यायालय को न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्तियों और जिला न्यायाधीशों के पदों से हीन पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाली विधि के अधीन विहित उनकी सेवा की शर्तों के अनुसार कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं करता है। सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून में निर्विवाद रूप से केवल अनुच्छेद 309 में निर्दिष्ट कानून का संदर्भ है। यह उपयुक्त विधानमंडल को किसी भी राज्य के मामलों के संबंध में लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। परंतुक राज्यपाल को ऐसी सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देता है जब तक कि उपयुक्त विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत उस संबंध में प्रावधान नहीं किया जाता है।"

यह सत्य है कि अनुच्छेद 309 संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन बनाया गया है और जहां तक यह हमारे प्रयोजन के लिए सुसंगत है, वह अनुच्छेद 234 है जो अनुच्छेद 309 को शासित करेगा, जिसका परिणाम यह है कि जहां न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की भर्ती के संबंध में नियम लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 234 के अनुसार राज्यपाल

द्वारा बनाए जाने हैं, उच्च न्यायालय में पदोन्नति सहित अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रयोग ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले कानून के अनुसार किया जाएगा और जब तक ऐसी सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा अनुच्छेद 309 के तहत ऐसा कानून नहीं बनाया जाता है। इसके बाद जो होना चाहिए वह यह है कि उपरोक्त अधीनस्थ न्यायिक सेवा में पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जा सकती है। अनुच्छेद 309 के अनुसार, ऐसे नियम राज्यपाल द्वारा लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय के परामर्श से बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है। "(Emphasis supplied).”

इसलिए उपरोक्त निर्णय और पहले की गई चर्चा का अनुपात स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के इस तर्क का समर्थन करता है कि राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए और अनुलग्नक सी और सी 1 में निहित निर्देश अधीक्षक के पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि यह राज्य सरकार की शक्ति के भीतर इन निर्देशों को जारी करने के लिए है जो जिला और सत्र न्यायाधीशों के न्यायालयों के मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित हैं। यह निष्कर्ष कि उपरोक्त निष्कर्ष प्रशंसनीय है, पूर्ण पीठ के निर्णयों के अनुपात से सामने आता है-मोडेम मोहन प्रसाद और एक अन्य बनाम बिहार सरकार (19) और बिहार राज्य बनाम मदन मोहन प्रसाद और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय। (20). उपरोक्त मामले में पटना उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय में निहित नियंत्रण की शक्ति के कारण वरिष्ठता निर्धारित करने की शक्ति है, लेकिन उच्च न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना होगा। दूसरे शब्दों में, निहितार्थ यह है कि सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठता पर काम करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दृष्टिकोण को बरकरार रखा जब बिहार राज्य ने अपील की और इस प्रकार फैसला सुनाया-

"चूंकि इस संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय में पुष्टि की शक्ति निहित करता है, इसलिए यह तर्कपूर्ण है कि सेवा में वरिष्ठता निर्धारित करने की शक्ति उच्च न्यायालय के पास भी है। बेशक, वरिष्ठता निर्धारित करने में उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल द्वारा वैध रूप से बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है।”

(19) A.I.R. 1970 पटना 432.

(20) 1976 S.L. साप्ताहिक रिपोर्टर 30.

(55) इस स्तर पर पंजाब और हरियाणा में सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों और जिला और सत्र न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ को संबोधित 20 नवंबर, 1969 के पत्र में निहित उच्च न्यायालय के निर्देशों के दायरे पर विचार करना उचित होगा, क्योंकि उत्तरदाताओं का मामला इस पत्र पर आधारित है। यह पत्र प्रत्यर्थियों के इस तर्क का आधार है कि अनुलग्नक सी और सी1 में निहित सरकार के निर्देश केवल प्रारंभिक नियुक्ति को विनियमित करने के लिए हैं और अधीक्षकों की नियुक्ति पर लागू नहीं होते हैं। इस पत्र में जिला और सत्र न्यायाधीश के अधीक्षक पद का कोई उल्लेख नहीं है और इस पत्र में केवल इतना ही कहा गया है कि जिला और सत्र न्यायाधीश से जुड़े प्रतिष्ठान में नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए कुछ प्रतिशत पदों के आरक्षण से संबंधित सरकारी अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए। चूंकि यह पत्र जिला और सत्र न्यायाधीशों को संबोधित है, इसलिए स्पष्ट निहितार्थ यह है कि संदर्भ केवल उन पदों के लिए है जिन पर जिला और सत्र न्यायाधीशों द्वारा नियुक्तियां की जानी हैं, न कि उन पदों के लिए जिनके

संबंध में नियुक्ति की शक्ति उच्च न्यायालय के पास है। इसलिए इस पत्र में उल्लिखित उच्च न्यायालय का निर्णय जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के अधीक्षकों के पदों पर लागू नहीं होता है।

यह मानते हुए कि प्रारंभिक भर्ती के मामलों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए कुछ प्रतिशत पदों के आरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय का निर्णय केवल अधीक्षकों के पदों पर भी लागू होता है, यह निष्कर्ष निकालना कि क्या यह निर्णय प्रश्न को नियंत्रित करेगा या राज्य सरकार के निर्देश लागू होंगे, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (4) की व्याख्या पर निर्भर करेगा। अनुच्छेद 16 के तहत राज्य को ऐसा कोई कानून या नियम बनाने से मना किया गया है जो सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता को छीन ले। हालाँकि, यह निषेध केवल राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के संबंध में है। इसके लिए अनुच्छेद 16 के खंड (4) द्वारा एक अपवाद बनाया गया है जो राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जिसका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। खंड (1) और (4) दोनों के तहत राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति पर जोर दिया जाता है और, अनुच्छेद 12 के साथ पढ़ने पर, इन खंडों से पता चलता है कि राज्य के तहत सेवा या रोजगार का अर्थ भारत की सरकार और संसद के तहत, राज्यों की सरकार और विधानसभाओं के तहत और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों के तहत सेवा या नियुक्ति है। दत्तात्रेय मोतीराम बनाम बॉम्बे राज्य (21) में "अधीन" शब्द के प्रभाव पर विचार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति या नियुक्ति से पता चलता है कि "नियुक्ति" शब्द को "रोजगार" शब्द के साथ पढ़ा जाना चाहिए और ऐसी नियुक्ति या रोजगार इंगित करता है कि इस प्रकार नियुक्त या नियोजित व्यक्ति राज्य के अधीनता का पद रखता है। गजुला दशरथ राम राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य में, (22) यह निर्णय दिया गया था कि अनुच्छेद 16 के खंड (1) और (2) में "राज्य के अधीन पद" अभिव्यक्ति उन कार्यालयों तक सीमित नहीं है जिन पर भाग XIV के प्रावधान लागू होते हैं, लेकिन उन कार्यालयों पर लागू होता है जिन पर भाग XIV लागू नहीं हो सकता है। अतः इन दोनों निर्णयों के अनुपात से यह होगा कि उन पदों के संबंध में जिन पर संविधान का भाग XIV लागू होगा अनुच्छेद 16 (1) लागू है और राज्य सरकार के अधीनस्थ पदों पर आसीन व्यक्तियों को राज्य के अधीन पद धारण करने के लिए अभिनिर्धारित किया जाएगा और उन व्यक्तियों के संबंध में राज्य सरकार पिछड़े वर्गों या नागरिकों के पक्ष में पदों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान कर सकती है।

(21) बम। L.R. 322

(22) A.I.R. 1961 S.C. 564.

(57) उपरोक्त के आलोक में जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के अधीक्षकों के पदों के संबंध में स्थिति की जांच करते हुए, यह पता चलेगा कि इन नियुक्तियों को करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है और यह कि उच्च न्यायालय इन नियुक्तियों को करते समय 23 जून, 1937 और 18 जुलाई, 1939 की अधिसूचनाओं और इन अधिसूचनाओं के तहत बनाए गए नियमों और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्राधिकरण के तहत एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इससे यह आवश्यक होगा कि जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालय के अधीक्षकों के पद राज्य सरकार के अधीनस्थ पद हैं और इसलिए राज्य सरकार अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत प्रावधान करने के लिए उचित प्राधिकारी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायपालिका और उच्च न्यायालय को कुछ परिस्थितियों

और स्थितियों में अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन उन कर्मचारियों के संबंध में अनुच्छेद 16 के खंड (4) के तहत कार्य करना राज्य सरकार की शक्ति के भीतर है जो भाग XIV द्वारा कवर किए गए हैं और जो इसके अधीन होने की स्थिति में हैं। इसलिए, अनुलग्नक सी और सी1 में निहित निर्देशों को जारी करने की राज्य सरकार की क्षमता चुनौती से परे प्रतीत होती है और उच्च न्यायालय को जिला और सत्र न्यायाधीशों के लिए न्यायालयों के अधीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनका पालन करना आवश्यक है।

(58) यह हमें प्रत्यर्थी के वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर लाता है कि याचिकाकर्ता को याचिका में क्लर्क के पद से पदोन्नति के पद के रूप में माना गया है, इस पद को लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह पद नियुक्ति द्वारा भरा जाता है न कि पदोन्नति द्वारा। इस तर्क का उद्देश्य यह याचिका दायर करने के लिए एक अवरोध पैदा करना है कि ये पद राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्ति या भर्ती द्वारा भरे जाते हैं और इसलिए राज्य सरकार को इन नियुक्तियों के संबंध में नियम बनाने या उस क्षेत्र को कवर करने वाले निर्देश जारी करने का अधिकार है जिसके बारे में कोई नियम नहीं हैं। हालाँकि, मैं इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित है कि अभिवचनों का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए और याचिका की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए जैसे कि यह एक क़ानून हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पैरा 4 और 6 और कुछ अन्य पैराओं में याचिकाकर्ता ने यह धारणा व्यक्त की है कि अधीक्षक का पद लिपिक से पदोन्नति का पद था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इन पैराओं में 'पदोन्नति' शब्द का उपयोग उच्च स्थिति और परिलब्धियों को इंगित करने के लिए किया गया है, न कि उस अर्थ में जिसे अनुच्छेद 235 में समझा गया है। इस निष्कर्ष पर पहुँचने पर मुझे इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि कुछ अन्य पैराओं में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अधीक्षक के पद का हकदार था और इस पद के लिए उस पर विचार करने से इनकार करना अनुच्छेद 16 (1) और (4) का उल्लंघन है और इस प्रकार उसने इस पद को एक उच्चतर लेकिन अलग पद के रूप में माना है जिसे नियुक्ति द्वारा भरा जाना है न कि पदोन्नति द्वारा जिस तरह से अध्याय 18-ए, खंड 1, उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम VI के तहत पदों को भरा जाता है, जो जिला न्यायालयों में अन्य मंत्री पदों से संबंधित है। इसलिए, मैं यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हूं कि याचिकाकर्ता को यह तर्क उठाने से वर्जित किया गया है कि राज्य सरकार अनुच्छेद 16 (1) और (4) के तहत अनुलग्नक सी और सी1 में निहित निर्देश जारी कर सकती है।

(59) ऊपर की गई चर्चा के परिणामस्वरूप, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता सफल होने का हकदार है और परिणामस्वरूप मैं इस याचिका को अनुमति देता हूं और अनुलग्नक पी और पी 1 को रद्द करता हूं और निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ता के मामले पर परिनिर्देशक के पद के लिए विचार किया जाए। हालांकि, पार्टियों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

बहुमत की राय को देखते हुए, यह रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रश्मीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

गुरुग्राम, हरियाणा